- 19th Year
- Issue: 251
- 18.01.2026 (SUNDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

जहां गोलियों की गूंज थी, आज वहां संगीत, नरेंद्र मोदी-बोले राज्य बना रहा नई पहचान

गुवाहाटी १७/०१ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में आयोजित बोडो समुदाय के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बागुरुज़्बा द्वौ 2026 में भाग लिया, जहां उन्होंने पारंपरिक वाद्य यंत्र सेर्जा बजाने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को सज़्मानित किया गया। इस अवसर पर बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकार एक साथ मिलकर बागुरुज़्बा नृत्य प्रस्तुत किया। मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि असम की संस्कृति, यहां की बोडो परंपराओं को करीब से देखने का अवसर मिलता रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर जितनी बार मैं असम आया हूं, पहले कोई और पीएम इतनी बार नहीं आया है।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी हमेशा यह इच्छा रही है कि असम की कला और संस्कृति को बड़ा मंच मिले।

भव्य आयोजनों के जरिए इसकी पहचान देश और दुनिया में बने। इसके लिए पहले भी लगातार प्रयास होते रहे हैं। बड़े स्तर पर बिहू से जुड़े आयोजन हों, दिल्ली में सवा साल पहले हुआ भव्य बोडोलैंड महोत्सव हो या दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हों। असम की कला और संस्कृति में जो अद्भुत आनंद है, उसे पाने का मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता हूं।

मोदी ने कहा कि बागुरुज़्बा दहोउ, ये केवल एक उत्सव नहीं है, ये एक माध्यम है, हमारी महान बोडो परंपरा को सज़्मान देने का। ये एक माध्यम है, बोडो समाज की महान विभूतियों को याद करने का। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार, असम की हर विरासत, हर गौरव का सज़्मान अपना सौभाग्य समझती है। संयोग से आज ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि असम का आत्मविश्वास, असम का सामर्थ्य और असम की प्रगति से भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई शक्ति मिल रही है। आज असम तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। असम की अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। इस विकास में, इस बदलाव में बोडोलैंड और यहां के लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं यह सोचकर भावुक हो रहा हूं कि मेरा असम कितना आगे बढ़ रहा है। एक समय, जहां आए दिन रक्तपात होता था, आज वहीं संस्कृति के अद्भुत रंग सज रहे हैं। एक समय, जहां गोलियों की गूंज थी, आज वहां खाम और सिफुंग की मधुर ध्वनि है। पहले जहां कर्फ्यू का सन्नाटा होता था, आज वहां संगीत के सुर गूंज रहे हैं। पहले जहां अशांति और अस्थिरता थी, आज वहां बागुरुज़्बा की ऐसी प्रस्तुतियां होने जा रही हैं। ये उपलज़्धि सिर्फ असम की नहीं है, पूरे भारत की है। असम के इस बदलाव पर हर देशवासी को गर्व है।मोदी ने कहा कि 2020 के बोडो शांति समझौते ने वर्षों से चले आ रहे संघर्ष पर विराम लगाया। इस समझौते के बाद भरोसा लौटाज और हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुज़्यधारा को अपना लिया। प्रतिभाशाली बोडो युवा आज असम के सांस्कृतिक दूत बन रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी बोडो समाज के बेटे-बेटियां नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम असम की कला, संस्कृति और पहचान का सज़्मान करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें तकलीफ हो जाती है। असम का सज़्मान किस पार्टी के लोगों को अच्छा नहीं लगता — कांग्रेस पार्टी। वो कौन सी पार्टी है, जिसने भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न देने का विरोध किया था — कांग्रेस पार्टी। असम में सेमीकंडज़्टर यूनिट का विरोध किस पार्टी ने किया था — कांग्रेस के कर्नाटक सरकार के मंत्री ने।

अल-फलाह विवि का आतंकी कनेज़्शन! ईडी का खुलासा-लाल किला ज़्लास्ट के आरोपी को दी नौकरी

१७/०१ (संवाददाता): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और कुलाधिपति जवाद अहमद सिद्दीकी को एक व्यापक आरोपपत्र में मुज़्य आरोपी बनाया है, जिसमें एक बड़े नियामक और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले का आरोप लगाया गया है - जिसमें लाल किला विस्फोट मामले के एक प्रमुख आरोपी को अनिवार्य सत्यापन के बिना विश्वविद्यालय के पद पर नियुक्त करना शामिल है। पिछले साल नवंबर में आतंकी मॉड्यूल के खात्मे के बाद अल-फलाह विश्व विद्यालय जांच के दायरे में आ गया था। दिल्ली बम धमाके के सिलसिले में विश्वविद्यालय से जुड़े चार डॉज़्टरों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे, जबकि कई अन्य लोगों से पूछताछ कर उन्हें गिरज़्तार किया गया था। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जवाद अहमद सिद्दीकी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरज़्तार किया गया था और धमाके से उनके संबंध की भी जांच चल रही थी।

अभियोजन पक्ष की शिकायत के अनुसार, ईडी का दावा है कि उसने एक विस्तृत योजना का पर्दाफाश किया है जिसमें विश्वविद्यालय और उसके मेडिकल कॉलेज कथित तौर पर फर्जी नियमों का पालन कर रहे थे।

कथित उल्लंघनों में फर्जी डॉज़्टर और फर्जी मरीज, जाली दस्तावेज और विदेशों में धन का हस्तांतरण शामिल हैं। जांचकर्ताओं का आरोप है कि सिद्दीकी नियुक्तियों, विज़ और नियामकों के साथ व्यवहार पर प्रत्यक्ष और केंद्रीकृत नियंत्रण रखते थे। ईडी सूत्रों का आरोप है कि अल-फलाह विश्व विद्यालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के मानदंडों को पूरा करने के लिए दर्जनों डॉज़्टरों को केवल कागजों पर पूर्णकालिक संकाय सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया था। जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों से पता चलता है कि इनमें से कई संकाय सदस्यों ने कभी भी परिसर में अपनी जिज़्मेदारियां नहीं निभाई।

बदायूं में दो सांडों के सामने आने से मालगाड़ी का डिज़्बा पटरी से उतरा

बदायूं १७/०१ (संवाददाता): बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र में बितरोई रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात बदायूं से कासगंज जा रही एक मालगाड़ी के सामने अचानक दो सांडों के आ जाने के कारण उसका एक डिज़्बा पटरी से उतर गया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

इस घटना के कारण बरेली-बदायूं -कासगंज रेल मार्ग पर कई ट्रेन का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। उन्होंने बताया कि भीषण कोहरा और जीरो दृश्यता के चलते राहत व मरज़्मत कार्य में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

रेलवे की राहत व मरज़्मत टीम के प्रयास से शनिवार सुबह तक इस मार्ग पर ट्रेन सेवा बहाल कर दी गई। इस दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। हालांकि, दोनों सांडों

की मालगाड़ी की चपेट में आकर मौत हो गई।बदायूं के वरिष्ठ स्टेशन मास्टर (एसएसएम) अफसर हुसैन ने बताया कि शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात को बितरोई रेलवे स्टेशन के बदायूं से कासगंज जा रही एक मालगाड़ी के सामने अचानक से दो सांड आ गए और मालगाड़ी से टकराने से उनकी मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि सांडों के अवशेष फंसने से इंजन के बाद वाला डिज़्बा पटरी से उतर गया, जिससे रेल मार्ग बाधित हो गया और कई घंटे यातायात प्रभावित रहा। उन्होंने बताया कि शून्य दृश्यता के कारण मरज़्मत कार्य में कुछ दिक्कत आई किंतु कासगंज और बरेली से आई राहत व मरज़्मत टीम ने कुछ घंटे में ही पटरी की मरज़्मत करके मालगाड़ी को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद रेल यातायात पूरी तरह से सामान्य हो गया।

एसजीपीसी ने आतिशी की सिख गुरुओं के लिए टिप्पणियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

नयी दिल्ली १७/०१ (संवाददाता): शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा के समाप्त हुए शीतकालीन सत्र में आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी द्वारा सिख गुरुओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर निंदा की है।अधिकारियों ने बताया कि एसजीपीसी की कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने की। इस बैठक में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी द्वारा कथित तौर पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया। पिछले साल गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर छह जनवरी को दिल्ली विधानसभा सत्र में चर्चा के बाद आतिशी द्वारा सिख गुरुओं के प्रति कथित तौर पर अनादर का मुद्दा एक बड़े राजनीतिक विवाद में तज़्दील हो गया है, जिसमें दिल्ली में सज़ारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पंजाब में आम आदमी पार्टी शामिल हैं।धामी ने कहा, दिल्ली विधानसभा में एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा सिख गुरुओं के बारे में अपमानजनक का प्रयोग सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। आम आदमी पार्टी के नेता के इस निंदनीय रवैये के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये खैरात नहीं, पंजाब का हक है, अमित शाह से बोले भगवंत मान, बॉर्डर पर उठाया बड़ा मुद्दा

चंडीगढ़ १७/०१ (संवाददाता): पंजाब के मुज़्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित मुद्दों और राज्य से जुड़े अन्य लंबित मामलों पर चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब के अधिकार केंद्र के समक्ष स्पष्ट रूप से रखे गए हैं। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मान ने बताया कि चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा सीमा बाड़ के पार स्थित कृषि भूमि का पुनर्वास था। उन्होंने मौजूदा सीमा बाड़ की समीक्षा का अनुरोध किया, जिसके कारण बाड़ और वास्तविक अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच काफी कृषि भूमि अलग-थलग पड़ गई है, जिससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें पहचान पत्र दिखाने के बाद बीएसएफ के साथ सज़्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अपनी जमीन पर खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मान ने कहा कि यदि बाड़ को फिर से व्यवस्थित किया जाता है, तो हजारों एकड़ जमीन भारतीय सीमा में आ जाएगी, जिससे किसान बिना किसी डर, प्रतिबंध या सुरक्षा चिंताओं के खेती कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि शाह ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उन्हें आश्वासन दिया कि इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि यह पंजाब का हिस्सा है और पंजाब का अधिकार है—यह कोई दान नहीं है। हम पंजाब के हक की मांग करने आए हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में उन्होंने बहुत सकारात्मक रुख अपनाया। बाड़ के बाहर बहुत सी जमीन है, जो कई जगहों पर दो से तीन किलोमीटर अंदर है।

मान ने पत्रकारों से कहा कि ऐसी जमीन भी है जहां किसान अपना पहचान पत्र दिखाकर बीएसएफ के साथ खेती करने जाते हैं। अगर बाड़ को 200-300 किलोमीटर आगे बढ़ा दिया जाए, तो हजारों एकड़ जमीन बाड़ के इस तरफ आ जाएगी। तब बिना किसी डर, सुरक्षा संबंधी चिंताओं या प्रतिबंधों के खेती की जा सकेगी। आज उन्होंने कहा कि इस पर फैसला लिया जाएगा, और मैं आभारी हूं कि वे मेरे अनुरोध पर इस पर विचार कर रहे हैं।

सुवेंदु ने ममता पर ठोका 100 करोड़ का मानहानि केस, कोयला घोटाले के आरोपों पर छिड़ी कानूनी जंग

कोलकाता १७/०१ (संवाददाता):पश्चिम बंगाल में राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में एक बड़े मोड़ के तहत, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आधिकारिक तौर पर ?100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा 16 जनवरी, 2026 को कोलकाता की अलीपुर कोर्ट में दायर किया गया है। यह कानूनी कार्रवाई ममता बनर्जी द्वारा 8 और 9 जनवरी, 2026 को दिए गए सार्वजनिक बयानों के कारण हुई है।

इन भाषणों के दौरान, मुज़्यमंत्री ने कथित तौर पर सुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक अवैध कोयला तस्करी रैकेट से जोड़ा था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अधिकारी ने कहा कि बनर्जी को भेजे गए मानहानि नोटिस का जवाब न

मिलने के बाद उन्होंने यहां अलीपुर में दिवानी न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन की अदालत में मुकदमा दायर किया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक ने सोशल मीडिया मंच 'एज़्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''ममता बनर्जी, मैं अपने वचनों का सज़्मान करता हूं जबकि आप मुद्दों और लोगों को भ्रमित करती हैं।कथित कोयला घोटाले में मेरी संलिप्तता को लेकर आपके घृणित और मनगढ़ंत आरोपों के संबंध में भेजे गए मानहानि नोटिस पर आपकी भ्रामक चुप्पी आपको इस स्थिति से उबरने में मदद नहीं करेगी।'' अधिकारी ने उनके द्वारा दायर वाद के पंजीकरण की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 卐मैंने आपकी धोखेबाज़ साज़िश को लेकर आपको अदालत तक घसीटने का अपना वादा निभाया और आज आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। इस मुकदमे का समय बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्योंकि पश्चिम बंगाल 2026 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है। यह कानूनी टकराव एक हज़्ते के भारी तनाव के बाद हुआ है.

मुंबई में सिर्फ दो भाई एकनाथ और देवेंद्र, जयचंद पर शिवसेना का पलटवार-पार्टी टूटने के असली जिमेदार संजय राउत

मुंबई १७/०१ (संवाददाता): शिवसेना प्रवक्ता सुसीबेन शाह ने शनिवार को महाराष्ट्र के उपमुज़्यमंत्री एकनाथ शिंदे को %जयचंद% कहने पर संजय राउत की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी का विभाजन शिवसेना (यूबीटी) सांसद की वजह से हुआ है और उन्होंने राउत से पिछले कुछ वर्षों के अपने आचरण पर गौर करने को कहा। एएनआई से बात करते हुए शाह ने कहा, जहाँ तक संजय राउत का सवाल है, उन्हें पिछले कुछ वर्षों के अपने आचरण पर गौर करना चाहिए। उन्हीं की वजह से शिवसेना का विभाजन हुआ। उन्होंने महाराष्ट्र के नागरिकों का

आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) गठबंधन को बीएमसी चुनावों में सबसे बड़ा गठबंधन बनने में सहयोग दिया।शाह ने कहा कि सबसे पहले, मैं महाराष्ट्र के नागरिकों, मुंबई के नागरिकों को हमें शानदार जीत दिलाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। हम सबका साथ, सबका विकास और महा विकास की दिशा में काम करेंगे।उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भाजपा और शिवसेना से मिलकर बनी सज़ारूढ़ महायुति के पास बहुमत है और मुंबई में अपना मेयर नियुक्त करने के लिए पर्याप्त संज़्या बल है। महायुति के पास बहुमत है, संज़्या बल है और अपना मेयर नियुक्त करने के लिए पर्याप्त संज़्या बल है। उन्होंने कहा मुज़्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे साथ बैठकर एक सज़्मानजनक समाधान निकालेंगे। मुंबई में सिर्फ दो भाई हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। यह विवाद शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत द्वारा आज बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव परिणामों के बाद महाराष्ट्र के उपमुज़्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला करने के बाद सामने आया है।

राउत ने आरोप लगाया कि अगर शिंदे ने पार्टी के साथ 卐विश्वासघात卐 न किया होता तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शहर के नगर निकाय में कभी पैर नहीं जमा पाती। राउत ने यह भी कहा कि मराठी लोग शिंदे को 卐जयचंद卐 के रूप में याद रखेंगे। एक पोस्ट में राउत ने शक्तिशाली गहड़वाला वंश के राजपूत शासक जयचंद का ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए शिंदे पर विश्वासघात का आरोप लगाया। जयचंद लोककथाओं में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मुहज़्मद गोरी का साथ देने के लिए जाने जाते हैं।

विविध समाचार

चाबहार पोर्ट पर संकट टालने की कोशिश! 26 अप्रैल की समयसीमा से पहले अमेरिका से प्रतिबंधों में छूट मांग रहा है भारत

नयी दिल्ली १७/०१ (संवाददाता): भारत और ईरान के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर विदेश मंत्रालय (स्ध्र) ने शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को बड़ी जानकारी साझा की है। भारत सरकार ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि भारत इस प्रोजेज़्ट से बाहर हो गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत इस परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट पाने के लिए वाशिंगटन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25त्न टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिससे सिस्तान-बलूचिस्तान में ईरान के दक्षिणी तट पर रणनीतिक रूप से स्थित चाबहार पोर्ट के विकास में भारत की भूमिका को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं।

हालांकि अमेरिका ने इस प्रोजेज़्ट पर अपनी पिछली छूट रद्द कर दी थी, लेकिन उसने भारत को छह महीने की छूट दी, जो 26 अप्रैल, 2026 तक वैलिड है। विदेश मंत्रालय (स्ध्र) ने पुष्टि की कि भारत शर्तों को साफ करने और सुरक्षित तरीके से अपनी भागीदारी जारी रखने के लिए अमेरिका के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें प्रोजेज़्ट में सीधे जोखिम को कम करने के लिए अपने तय .120 मिलियन को ट्रांसफर करना शामिल है। एक और संभावना जिस पर चर्चा हो रही है, वह है चाबहार के विकास को जारी रखने के लिए एक नई इकाई बनाना, जबकि भारतीय सरकार के लिए जोखिम को कम से कम किया जाए। भारत इस प्रोजेज़्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ज़्योंकि यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (ढ्ढहस्ञ्जष्ट) में इसकी संभावित भूमिका है, जो भारत, ईरान, अफगानिस्तान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला 7,200 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है।

पिछले साल ईरान के साथ भारत का दो-तरफ़ा व्यापार .1.6 बिलियन था, जिसमें .1.2 बिलियन का निर्यात और 0.4 बिलियन का आयात शामिल था। अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने के बावजूद, सरकारी सूत्रों ने कहा कि नए टैरिफ का भारत के व्यापार पर बहुत कम असर पड़ने की उज़्मीद है।

विदेश मंत्रालय ईरान में स्थिति पर करीब से नज़र रख रहा है, जहाँ सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों में 2,500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है।

चाबहार पर बातचीत के बीच, ईरान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने सज़्त कदम उठाए हैंन्यात्रा न करने की सलाहन्स्ध्र ने भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है।

देश छोड़ने का निर्देशन्जो भारतीय नागरिक पहले से ईरान में हैं (लगभग 9,000 लोग, जिनमें छात्र और पेशेवर शामिल हैं), उन्हें उपलज़्ध व्यावसायिक उड़ानों के माध्यम से जल्द से जल्द ईरान छोड़ने को कहा गया है।ट्रंप प्रशासन का प्रभावन्अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25त्न अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी के बाद भारत के लिए यह %डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग% काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है। फिलहाल, लगभग 9,000 भारतीय, जिनमें ज़्यादातर छात्र हैं, ईरान में रहते हैं। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है और वहाँ रहने वालों से उपलज़्ध साधनों से देश छोड़ने का आग्रह किया है। जायसवाल ने ज़ोर देकर कहा कि तेहरान में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में है।

ईरान में अशांति ईरानी मुद्रा में गिरावट के बाद शुरू हुई, जो आर्थिक शिकायतों से राजनीतिक बदलाव की मांगों में बदल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखती है तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी।भारत के लिए चाबहार न केवल व्यापारिक बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 26 अप्रैल 2026 की समयसीमा से पहले भारत का मुज़्य उद्देश्य एक ऐसा स्थायी कूटनीतिक समाधान निकालना है जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा टल जाए और क्षेत्रीय कनेज़्टिविटी बाधित न हो।

विराट रामायण मंदिर में आज स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग

मोतिहारी १७/०१ (संवाददाता): बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। मंदिर परिसर में आज दुनिया के सबसे भारी और विशाल शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। काले ग्रेनाइट पत्थर से बने इस शिवलिंग का वजन 210 टन है, जबकि इसकी ऊंचाई और गोलाई 33 फीट है। इस भव्य प्राण-प्रतिष्ठा और स्थापना कार्यक्रम में बिहार के मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष रूप से शिरकत करेंगे। शिवलिंग का आकार और वजन इतना अधिक है कि इसे स्थापित करना अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। इस महाकाय शिवलिंग को उठाने और सही स्थान पर रखने के लिए विशेष प्रकार की दो क्रेनें मंगाई गई हैं। इन क्रेनों की क्षमता क्रमश: 700 टन और 500 टन है, जिन्हें विशेष तौर पर बंगाल और भोपाल से मोतिहारी लाया गया है। मंदिर प्रशासन ने स्थापना को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं।

विराट रामायण मंदिर के निर्माण के लिए पूर्वी चंपारण के कैथवलिया गांव को चुने जाने के पीछे एक पौराणिक महत्व है। स्थानीय साधु-संतों के अनुसार, त्रेतायुग में जब भगवान श्रीराम माता सीता से विवाह के उपरांत जनकपुर से अयोध्या लौट रहे थे, तो उनकी बारात का एक रात्रि विश्राम इसी स्थान पर हुआ था। लोक मान्यताओं के मुताबिक, चूंकि यहां रामजी की 'बहू' (माता सीता) का ठहराव हुआ था, इसलिए कालांतर में पास के गांव का नाम 'बहुआरा' पड़ गया। मंदिर की चौहद्दी के पूर्व दिशा में बहुआरा गांव आज भी मौजूद है और निर्माणाधीन राम-जानकी पथ इसी रास्ते का अनुसरण कर रहा है।

विराट रामायण मंदिर न केवल अपने शिवलिंग के लिए, बल्कि अपनी विशालता के लिए भी विश्व विज़्यात होगा। 150 एकड़ के लक्ष्य के साथ, फिलहाल 120 एकड़ में फैले इस परिसर में कुल 22 मंदिर और 12 शिखर बनाए जाएंगे। मुज़्य मंदिर की लंबाई 1080 फीट और चौड़ाई 540 फीट होगी। मंदिर का मुज़्य शिखर सबसे ऊंचा होगा, जिसकी ऊंचाई 270 फीट प्रस्तावित है। इसके अलावा परिसर की भव्यता बढ़ाने के लिए एक 190 फीट का शिखर, चार 180 फीट के शिखर, एक 135 फीट का और पांच 108 फीट ऊंचे शिखर बनाए जाएंगे। इस भव्यता की झलक पाने के लिए अभी से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है।

यह मंदिर भौगोलिक रूप से भी दो पवित्र धामों को जोड़ने वाली कड़ी बनेगा। प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या और माता सीता की जन्मभूमि जनकपुर (नेपाल) के बीच मोतिहारी के कैथवलिया में यह मंदिर आकार ले रहा है, जिसके आसपास के क्षेत्र का नामकरण 'जानकी नगर' किया गया है। राम-जानकी पथ मार्ग से अयोध्या से इस मंदिर की दूरी 315 किलोमीटर और जनकपुर धाम से करीब 115 किलोमीटर है। वहीं, राजधानी पटना से यह 120 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर भविष्य में राम-जानकी मार्ग पर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का एक प्रमुख केंद्र होगा।

दिल्ली सरकार का बड़ा संकल्प, रेखा गुप्ता ने अगले 4 वर्षों में प्रदूषण कम करने के लिए पेश किया मास्टर प्लान

नयी दिल्ली १७/०१ (संवाददाता): दिल्ली की मुज़्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्य योजना की घोषणा की। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य अगले चार वर्षों के भीतर दिल्ली के वायुमंडल में मौजूद क्क्रू 2.5 के स्तर को न्यूनतम स्तर पर लाना है।

रेखा गुप्ता ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कई विभागों को शामिल करते हुए एक कार्य योजना प्रस्तुत की और अधिकारियों को 'स्पष्ट और परिणामों पर केंद्रित' तरीके से काम करने का निर्देश दिया। पीएम 2.5 हवा में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं जो सांस के साथ शरीर में फेफड़ों तक जा सकते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। गुप्ता ने कहा, ''प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लंबी है; हमारी सरकार चार साल की अवधि में वायु प्रदूषण (पीएम 2.5) के स्तर को काफी हद तक कम करने के लिए एक स्पष्ट, और परिणामों पर केंद्रित कार्य योजना पर काम कर रही है।

मुज़्यमंत्री ने दिल्ली के विभिन्न विभागों (लोक निर्माण विभाग, परिवहन, और पर्यावरण मंत्रालय) के अधिकारियों के साथ बैठक कर एक सज़्त रोडमैप तैयार किया है।

मुज़्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कण, जो फेफड़ों के लिए सबसे घातक माने जाते हैं, सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं।

अंतर-विभागीय समन्वयन्विभिन्न विभागों को %स्पष्ट और परिणामों पर केंद्रित% (ष्द्यद्गड्डह्म् ड्डठ्ठस्र ऋद्ग-ह्यह्वद्यह्ल-शह्लद्बद्गठ्ठह्लद्गस्र) तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने अगले चार वर्षों की एक निश्चित अवधि तय की है, जिसके दौरान प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का प्रभाव जमीन पर दिखना चाहिए।

ये कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए फेफड़ों की गहराई तक चले जाते हैं और रक्त प्रवाह (ड्ढद्यशशस्त्र-ह्यह्लह्द्गड्डद्व) में भी मिल सकते हैं। इससे हृदय रोग, अस्थमा और सांस संबंधी अन्य गंभीर बीमारियाँ होने का खतरा रहता है।

अब नहीं चलेगा टीएमसी का तुष्टिकरण, मालदा रैली से नरेंद्र मोदी का सीधा संदेश

मालदा १७/०१ (संवाददाता): प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्वी भारत दशकों से घृणा की राजनीति के कारण पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति विकास को रोकती है और लोगों को अवसरों से वंचित करती है। उन्होंने आगे कहा कि इस क्षेत्र की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए विकास-केंद्रित शासन आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्वी भारत का विकास आवश्यक है। मालदा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास एक विकसित भारत के निर्माण की कुंजी है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवेंदु शेखर राय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मालदा की पहचान को संरक्षित करने में उनके प्रयासों की सराहना की। एक जनसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के लिए राय के योगदान को स्वीकार किया और स्थानीय विरासत को विकास और सांस्कृतिक गौरव की व्यापक कहानी से जोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और हिंसा की पार्टी के रूप में बेनकाब हो चुकी है। मालदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को ऐसी भाजपा सरकार की जरूरत है जो विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता दे। प्रधानमंत्री ने सत्ताधारी पार्टी पर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया और राज्य में राजनीतिक परिवर्तन का आह्वान किया।प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि भाजपा ने पूर्वी राज्यों को विभाजनकारी और नफरत से प्रेरित राजनीति के चंगुल से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का ध्यान विकास, अवसंरचना निर्माण और जन कल्याण पर केंद्रित है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि इन प्रयासों से पूर्वी भारत देश की विकास गाथा में और अधिक मजबूती से जुड़ रहा है।

अचानक 114 राफेल विमान खरीदने की जरूरत ज़्यों पड़ गयी? इस सौदे में भारत ने ज़्या शर्तें रखी हैं?

नयी दिल्ली १७/०१ (संवाददाता): भारत की सेनाओं को आधुनिक हथियारों और अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने, सीमाओं की सुरक्षा को अभेद्य बनाने और हर मोर्चे पर दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पीछे नहीं रहते। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उनकी नीति साफ है कि ताकत ही शांति की सबसे मजबूत गारंटी होती है। इसी सोच के तहत भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक और निर्णायक कदम अब आकार ले रहा है। राफेल लड़ाकू विमानों की संज़्या बढ़ाने की दिशा में सरकार की ताजा पहल न केवल वायुसेना की कमजोर पड़ती स्क्वाड्रन ताकत को संबल देगी, बल्कि बदलते सामरिक परिदृश्य में भारत को निर्णायक बढ़त भी दिलाएगी।

हम आपको बता दें कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाले रक्षा खरीद बोर्ड ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी औपचारिक प्रक्रिया का पहला ठोस चरण है, जिसके बाद प्रस्ताव रक्षा अधिग्रहण परिषद के सामने जाएगा और अंततन्प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति से अंतिम स्वीकृति मिलेगी। अनुमान है कि यह सौदा करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का होगा, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा बन सकता है।

यह मंजूरी ऐसे समय आई है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के भारत दौरे की तैयारी चल रही है। यदि मूल्य वार्ता और अन्य स्वीकृतियां समय पर पूरी होती हैं तो दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी समझौते के तहत सौदे पर हस्ताक्षर संभव हैं। इस मॉडल में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी और सीधे आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना पहले ही 36 राफेल विमानों का संचालन कर रही है और नौसेना ने भी इसी श्रेणी के 26 समुद्री संस्करण मंगाए हैं। नए सौदे के तहत 18 विमान सीधे उड़ान योग्य स्थिति में मिलेंगे, जबकि शेष का निर्माण भारत में होगा। नागपुर स्थित डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस में अंतिम संयोजन लाइन स्थापित होने की तैयारी है, जहां टाटा, महिंद्रा और डायनामेटिक टेज़्नोलॉजीज जैसी भारतीय कंपनियां साझेदार बनेंगी। स्वदेशी सामग्री की हिस्सेदारी 55 से 60 प्रतिशत तक रहने की उज़्मीद है।

हम आपको यह भी बता दें कि इस सौदे में भारत ने कुछ बड़ी शर्तें रखी हैं, जिनमें सभी विमानों पर भारतीय हथियारों और मिसाइलों का एकीकरण, सुरक्षित डेटा लिंक और एयरफ्रेम, इंजन तथा एवियोनिज़्स में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। राफेल के उन्नत स्न-4 और भविष्य के स्न-5 संस्करणों की मांग भी रखी गई है, जिनमें नई पीढ़ी का एईएसए रडार, बेहतर आत्म सुरक्षा प्रणाली, लंबी दूरी की मारक क्षमता और कृत्रिम बुद्धिमज़ा आधारित सहायता शामिल होगी। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब वायुसेना की स्क्वाड्रन संज़्या घटकर 29 रह गई है, जबकि स्वीकृत संज़्या 42 है। मिग-21 जैसे पुराने विमानों की विदाई और तेजस परियोजना में देरी ने यह अंतर और गहरा कर दिया है। चीन और पाकिस्तान के साथ दो मोर्चों की चुनौती और बांग्लादेश की ओर से उभरती सुरक्षा चिंता ने इस खरीद को अनिवार्य बना दिया है।

देखा जाये तो राफेल की बहु भूमिका क्षमता, गहरी मार, नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता और घातक सटीकता भारतीय वायुसेना को वह धार देती है जिसकी आज सज़्त जरूरत है। यह विमान हवा में प्रभुत्व स्थापित करने के साथ साथ जमीनी ठिकानों पर सर्जिकल वार और समुद्री क्षेत्र में भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

इस सौदे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भारत केवल उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि निर्माता बनेगा। एयरफ्रेम, इंजन और एवियोनिज़्स में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से भारतीय उद्योग को जबरदस्त बल मिलेगा। यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ठोस जमीन देता है और भविष्य की परियोजनाओं के लिए कौशल तथा आधारभूत ढांचा तैयार करता है। साथ ही बड़ी संज़्या में एक ही प्लेटफार्म होने से रखरखाव लागत घटेगी और उपलज़्धता बढ़ेगी। सामरिक परिदृश्य में इसका प्रभाव दूरगामी होगा। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स और पाकिस्तान की वायुसेना दोनों को अब ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना होगा, जो सेंसर, हथियार और नेटवर्क के स्तर पर उनसे आगे है। राफेल की तैनाती से भारत की निवारक क्षमता मजबूत होगी और किसी भी दुस्साहस की कीमत दुश्मन के लिए असहनीय बनेगी। बहरहाल, राफेल सौदा भारत के संप्रभु निर्णय का प्रतीक है। यह बताता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत अब निर्णायक प्रतिकार की पूरी तैयारी कर चुका है यही संदेश राफेल के पंखों पर सवार होकर आसमान में गूंजेगा।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

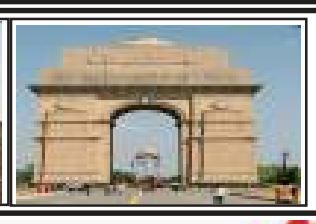

विविध समाचार

सफलता की होड़ में उधड़ते मानवीय रिश्ते

पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव ने हमारे देश में भौतिकवाद को प्रोत्साहन दिया है और अब तो पढ़े लिखे हों या नहीं सभी सुख-सुविधाओं के जाल में फंसते जा रहे हैं। भारतीय अध्यात्म ज्ञान के बारे में जानते सभी हैं पर उसे धारण करना लोगों को अब पिछड़ापन दिखाई देता है। नतीजा यह है कि समाज में आपसी रिश्ते एक औपचारिकता बनकर रह गए हैं।

सिर्फ सांसारिक शिक्षा काफी नहीं

अक्सर अनेक लोग शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं अथवा उनकी देखभाल नहीं करते। इसके दो कारण होते हैं एक तो यह कि नए सामाजिक परिवेश से तालमेल न बिठा पाने के कारण लोग अपने माता-पिता को त्याग देते हैं या फिर वह व्यवसाय के सिलसिले में उनसे दूर हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियों का विश्लेषण करने पर अनुभव होगा कि आधुनिक युग के समस्त माता-पिता अपने बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि वह इस मायावी दुनिया में उच्च से उच्च पद प्राप्त कर, अधिक से अधिक धनार्जन करें और भरपूर मान प्रतिष्ठा की दुनिया में चमककर उनका व अपना नाम रोशन करें। लोग बच्चों की कामयाबी के सपने देखते हैं और केवल सांसारिक शिक्षा तक ही अपने बच्चों को सीमित रखते हैं। किसी तरह अपना पेट पालो यही सिखाते हुए वह ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे कि वह दुनिया का कोई विशेष ज्ञान दे रहे हैं। यह तो एक सामान्य चतुराई है, जिसे सब जानते हैं।

सभी सुविधाओं के बाद भी अशांत रहता है मन

यह उन माता-पिता का भ्रम है कि शिक्षा तो सभी स्वतः ही प्राप्त करते हैं पर जिन बच्चों को उनके माता-पिता इसके साथ ही अध्यात्म ज्ञान, ईश्वर भक्ति और परोपकार करना सिखाते हैं वह अधिक योग्य निकलते हैं। जब तक आदमी के मन में अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह न तो स्वयं कभी प्रसन्न रह पाता है और न ही दूसरों को प्रसन्न करता है। आज समस्त सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी बहुत सभी लोगों का मन अशांत रहता है, क्योंकि मानव को परमात्मा के ज्ञान का प्रत्यक्ष बोधकर शांति, सत्य, अहिंसा एवं निःस्वार्थ प्रेम का वातावरण स्थापित करने का समय नहीं है। वह तो पैसे कमाने और सफलता की दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहते हैं। मनुष्य जीवन में भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा मिलती है पर उसका उपयोग नहीं कर हम उसे ऐसे ही नष्ट कर डालते हैं। ऐसे में वह ज्ञानी धन्य है जो दाल-रोटी खाकर पेट भरते हुए भगवान भजन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय निकालते हैं।

पश्चिमी देशों में नीले रंग को युवा लड़कों से जोड़कर देखा जाता है। भौतिक और भौगोलिक क्षेत्र में रंग सबसे सुंदर पहलुओं में से एक है। हम चारों तरफ रंगों से घिरे हुए हैं, लेकिन कितनी बार हम असंख्य रंगों में कई बारीकियों को नहीं देख पाते हैं। नीले रंग को हमारे यहां भी खास महत्व दिया गया है। रंगों की रहस्यमय रंगीन दुनिया को जानने के लिए वैज्ञानिक और दार्शनिक हमेशा से ही जिज्ञासु रहे हैं। हाल के दिनों में इस पर बहुत काम हुआ है। हाल ही में हुई रिसर्च में कहा गया है कि अगर आपको तुरंत निर्णय लेने में दिक्कत आती है तो आपको ब्लू लाइट में बैठना चाहिए।

युवाओं का नीला रंग...

रंगों का अपना चमत्कार होता है। उसका शरीर मन और भावना के स्तर पर बहुत प्रभाव होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन पर सूर्य की किरणों का गहरा असर होता है, वैसे ही रंगों का भी असर होता है। यह भी तो प्रकाश ही है। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जिस दिन आकाश बादलों से घिरा रहता है तब अग्नि मंद हो जाती है, शरीर सुस्ताने लग जाता है। धूप होती है, तो आदमी में स्फूर्ति होती है, सूरज के ताप का और प्रकाश का हमारे शरीर पर प्रभाव होता है, वैसे ही रंगों का प्रभाव भी हमारे शरीर और मन पर होता है। वर्तमान में रंगों पर बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है, अनेक प्रयोग और तथ्य सामने आए हैं। अगर आपको तुरंत निर्णय लेने में दिक्कत आती है तो आपको ब्लू लाइट में बैठना चाहिए: यह बात एक रिसर्च में सामने आई है। छोटी अवधि के लिए नीले रंग की रोशनी से संपर्क आपको कठिन निर्णय लेने में मदद कर सकता है। नीले रंग के प्रकाश में 40 मिनट तक रहने के बाद आप कठिन निर्णय तीव्रता के साथ ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में इस अध्ययन के शोधकर्ताओं के मुताबिक पिछले अध्ययनों में केवल प्रकाश में रहने की अवधि के दौरान उसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन यह अध्ययन बताता है कि नीले रंग के प्रकाश के आवरण के लाभकारी प्रभाव 40 मिनट बाद भी रहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के अध्ययन के निष्कर्षों के मुताबिक, आधा घंटे के लिए नीले रंग की रोशनी में एक छोटी अवधि का संपर्क अधिक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देने के समय में औसत दर्जे का परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त है। यह सुधार सीधे तौर पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की सक्रियता में औसत दर्जे के परिवर्तन के साथ जुड़े हैं। नीलापन युक्त सफेद रोशनी कई व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे पायलट कॉकपिट, ऑपरेशन कक्ष और सैन्य कार्यों में काफी इस्तेमाल की जाती है, जहां त्वरित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है।

नीले रंग की खूबियां

नीला रंग अपनी विशेष खूबियों के कारण काफी महत्व रखता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम तमाम जतन करते हैं। इस मामले में रंग भी हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि इनका संबंध स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियों से होता है। नीला रंग आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान, प्रेरणा और आंतरिक शांति का रंग है। नीले रंग के उपचार में दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से, ठंडा और तसल्ली के लिए प्रयोग किया जाता है। नीले रंग के प्रयोग से शांति का अनुभव होता है। नीले रंग का ध्यान करने से शांति मिलती है। इसी तरह बैंगनी रंग शक्ति के साथ सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों जुड़ा हुआ है।

नीले रंग के लाभ

फेंगशुई में नीले रंग को प्रगति और सकारात्मक परिवर्तन का रंग बताया गया है। इसका उचित तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह घर और उसमें रहने वाले सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ कराता है, चिंता से मुक्ति देता है और आर्थिक व बौद्धिक प्रगति प्रदान करता है। नीला रंग जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जल तत्व के सारे गुण इसमें समाहित हैं। नीला रंग पानी की ही तरह चंचल, गतिमान और जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करता है। फेंगशुई कहता है कि अगर अपने आसपास के वातावरण में नीले रंग का प्रयोग किया जाए तो यह आपकी इच्छापूर्ति में मदद करता है। यह आपके ठहरे हुए व्यवसाय, करियर या निजी संबंधों को फिर से गति प्रदान करने में सहायक होता है।

ताजे विचार

हल्का नीला रंग उन लोगों के लिए विशेष लाभदायक हो सकता है, जो सृजनात्मक कार्यों से जुड़े हैं। यह रंग ताजा विचारों को प्रोत्साहित करता है। सीखने के इच्छुक लोगों को भी यह रंग अपेक्षित लाभ प्रदान करता है। गहरा नीला रंग शयनकक्ष के लिए उपयुक्त रंग माना जाता है। शयनकक्ष में गहरा नीला रंग तनावमुक्त, गहरी और सुकूनभरी नींद प्रदान करता है। इस रंग की एक और खासियत है कि यह ब्लड प्रेशर के मरीजों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। नीला रंग ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में मददगार होता है। ऐसा माना जाता है कि रंगों का जन्म लगभग 2000 ईसा पूर्व हुआ। धीरे-धीरे रंगों की छटा पूरे विश्व में फैल गयी। भारत में प्रारम्भिक काल से ही रंगों का विशेष महत्व रहा है। मोहन जोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता में रंगीन बर्तन एवं मूर्तियां पाई गई।

मिस्र में नीला रंग

प्राचीन मिस्र में रंगों का उपयोग 'उपचार रंग' के रूप में भी किया गया। मिस्र निवासी सूर्य की उपासना किया करते थे। उनका मानना था कि सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन असंभव है। उन्होंने प्रकृति के रंगों के मुताबिक ही अपने मंदिरों को भी रंगा था। नीले आसमानी रंग से उनको काफी लगाव था। इनके कक्ष भी विभिन्न रंगों से सजे होते थे। आधुनिक चिकित्सा पद्धति को प्राचीन प्रकाश चिकित्सा से जोड़ कर देखा गया। रंगों की रहस्यमय रंगीन दुनिया को जानने के लिए वैज्ञानिक और दार्शनिक हमेशा से ही जिज्ञासु रहे। इसका सटीक अध्ययन सबसे पहले न्यूटन ने किया। उन्होंने यह कहकर सनसनी फैला दी कि रंग एक नहीं सात होते हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें एक अंधेरे कमरे में छोटे से छेद द्वारा सूर्य का प्रकाश आता था। यह प्रकाश एक प्रिज्म कांच द्वारा अपवर्तित होकर सफेद पर्दे पर पड़ता था। पर्दे पर सफेद प्रकाश के स्थान पर इन्द्रधनुष के सात रंग दिखाई दिए। ये रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी हैं। जब न्यूटन ने प्रकाश के मार्ग में एक और प्रिज्म पहले प्रिज्म से उलटा रखा, तो इन सात रंगों का प्रकाश मिलकर पुनः सफेद रंग प्रकाश बन गया। इन्हीं सात रंगों को इन्द्रधनुष नाम से जाना जाता है। सौ साल पहले पश्चिम में औद्योगिकरण की क्रांति ने कपड़ा उद्योग को तेजी से रफ्तार दी। जिससे रंगों की मांग बढ़ गई। प्राकृतिक रंगों के साधन भी सीमित थे। मांग और पूर्ति के आंकड़े को देखते हुए कृत्रिम रंगों की खोज शुरू हुई। उन्हीं दिनों रॉयल कालेज ऑफ केमिस्ट्री, लंदन में विलियम पार्किंसन एनीलीन से मलेरिया की दवा कुनैन बनाने में जुटे हुए थे। कई प्रयोगों के बाद कुनैन तो बना नहीं लेकिन बैंगनी रंग जरूर बन गया। 1856 ई. में संयोगवश तैयार हुए इस रंग को मोव कहा गया। इस क्रम में 1860 में रानी रंग, 1862 में एनलीन नीला और काला 1865 में बिस्माई भूरा, 1880 ई में सूती काला जैसे रासायनिक रंग उत्पन्न हुए। शुरुआत में यह रंग तारकोल की सहायता से बनाये जाते थे बाद में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाने लगा। जर्मन रसायनशास्त्री एडोल्फ वॉन ने 1865 में तमाम असफलताओं से जूझते हुए नील बनाने में सफलता प्राप्त की। जिसके लिए उन्हें 1905 ई. में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

आपकी जींस असली है या नकली?

आज के दौर में हर इंसान फैशन के साथ ब्रांडेड कंपनी के कपड़ों के पीछे भागता है जिसके लिए वह बड़ी कीमत देने को भी तैयार रहता है। ब्रांडेड कपड़े परफेक्ट लुक के साथ उभरते भी है। इसलिए लोग इनके पीछे ज्यादा भागते है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सही कीमत देने के बाद भी हम ब्रांडेड कपड़ों की खरीददारी करते समय धोखा खा ही जाते है। क्योंकि असली जैसी दिखने वाली ब्रांडेड चीज भी नकली हो सकती है। इसलिए आज हम आपको ऐसी जानकारी से अवगत करा रहे है। ब्रांड लेविस की जीन्स के बारे में जिसकी असलियत की पहचान कर आप धोखा खाने से बच सकते है। तो जाने जींस के असली नकली की पहचान आप किस प्रकार कर सकते है।

बटनों में खास मार्क

जो जीन्स असली होती है उसमें लगने वाली बटनों में खास तरह का मार्क लगा होता है। यदि आपकी जींस में उपयोग किया जाने वाला बटन प्लेन है तो तुरंत ही समझ जाइए की वह जींस नकली ब्रांड की है। हमेशा जींस में आपको लेविस का मार्क खास तरह से लगा हुआ मिलेगा।

555 नंबर

ब्रांड जीस की सही पहचान जानने के लिएउसके बटन मे इस बात पर गौर करे कि उसमें लिखा जाने वाला नं. 555 है या नहीं। अगर नहीं है तो आपकी जीस लेविस ब्रांड का नहीं है। वैसे तो बाजार में आपको अपनी ओर खींचने के लिए कई तरह के अलग अलग ब्रांड के जींस दिखाए जाते है। जो ज्यादातर नकली भी होते है।

डब्ल्यू33 एल 34

लेविस ब्रांड के जींस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें दिए लोगो में डाले गए अंक की लंबाई और चौड़ाई, खास तरह से लिखी होती है। इसमें डब्ल्यू33 एल 34 लिखा मिलेगा यदि आपकी जींस में इस प्रकार का नंबर नहीं है तो आपकी जींस नकली ब्रांड की है।

स्मार्ट लुक पाने के लिए चुनें सही चश्मा...

आजकल हर लड़के को चश्मा पहनना पसंद होता है। मार्केट में कई डिजाइन में चश्मे मिल जाते हैं, जो आपको स्मार्ट दिखने में मदद कर सकते हैं। वैसे अगर आप एक सही चश्मे का प्रयोग करते हैं तो उससे आप केवल स्मार्ट ही नहीं लगेंगे बल्कि इससे आपके अन्दर आत्मविश्वास भी आएगा। आप जब भी चश्मा लें तो पहले यह जरूर देख लें कि आपके चेहरे का आकार कैसा है। ज्यादातर चेहरे चार आकार के होते हैं। गोल, आयताकार, ओवल और हर्ट या डायमंड आकार। अगर आप अपने चेहरे के आकार को ध्यान में रख कर चश्मा लेते हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी और आप अपने लिए एक सही चश्मे का चुनाव कर सकेंगे। अपने चेहरे के आकार के साथ-साथ आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप जो चश्मा ले रहे हैं वो कहीं आपके चेहरे से बड़ा तो नहीं है। अगर आपका चेहरा छोटा है और आप हर समय चश्मा पहने रखते हैं तो हो सकता है बड़े चश्मे आपके चेहरे पर अच्छे न लगें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े चश्मे आपके चेहरे पर अच्छे नहीं लगेंगे। आप चाहें तो कभी-कभी अपने लुक में बदलाव करने के लिए बड़े चश्मों का भी प्रयोग कर सकते हैं।

ऑफिस में बने रहें मिस्टर कूल...

ऑफिस में काम करते समय कई बार लोगों को किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता है। किसी भी कारण तनाव का माहौल बन जाता है। काम के चलते कुछ न कुछ स्ट्रेस हो जाता है। ऑफिस में अपने डेस्क पर एक छोटे गमले पर हरा पौधा रखें। विशेषज्ञों का मानना है कि हरा पौधा देखने से मन को शांति मिलती है। एक छोटा हरा पौधा आपके चारों तरफ के माहौल में शांति फैलाता है। जब भी ऑफिस में आपको किसी बात पर गुस्सा आए या फिर काफी थकावट महसूस हो तब हरे पौधे की तरफ देखें एवं अच्छा सोचें। ऑफिस में काम को लेकर आए गुस्से पर काबू पाने के लिए अपनी कुर्सी से उठकर आसपास कुछ देर के लिए टहलें। ऐसा करने से काम से होने वाला स्ट्रेस दूर होता है। मांसपेशियां फैलती हैं और मन में पॉजिटिव विचार आते हैं। काम के फ्रस्टेशन को दूर करने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप कुछ हल्की एक्सरसाइज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑफिस में काम के बीच-बीच में ड्राइ फ्रूट्स खाने से काम से होने वाला स्ट्रेस कम होता है। साथ ही गुस्सा आने पर ड्राइ फ्रूट्स खाने से मेंटल प्रेशर कम होता है और गुस्सा जल्द ही ठंडा हो जाता है।

प्रेम और दया सबसे बेहतर रास्ता...

ईश्वर को खुश करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। मंत्र साधक लाखों बार मंत्र जप करते हैं, भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग मंदिर जाकर ईश्वर की पूजा करते हैं। धूप-दीप आरती से भगवान को प्रसन्न करने की भी कोशिश करते हैं। इतना करने के बाद भी यह पता नहीं होता कि ईश्वर हमें प्यार करता है या नहीं। प्रेम में सफलता तभी मिलती है जब हम जिसे प्यार करते हैं वह हमें प्यार करे। इसलिए हमेशा ऐसा काम करें जिससे ईश्वर आपको प्यार करे। यह काम पूजा-पाठ और मंत्र जप से भी आसान है। सभी धर्म एक बात पर सहमत हैं कि प्रेम और दया यह दो ऐसे साधन हैं जिसकी बदलौत हम ईश्वर को मजबूर कर सकते हैं कि वह हमें प्यार करे। प्रेम और दया ऐसी चीज है जिसके लिए न तो धन की जरूरत पड़ती है और न ही किसी दूसरे साधनों की। यह अपने आप में पूर्ण और पवित्र है।

प्रेम के बदले प्रेम

हम किसी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं तो बदले में हमें भी प्रेम मिलता है। इसका कारण यह है कि जिसके प्रति हम प्रेम दर्शाते हैं उसके हृदय में मौजूद आत्मा जो ईश्वर का स्वरूप होती है वह प्रसन्न होती है और बदले में हमें अपने प्रेम की अनुभूति कराती है। गीता, कुरान अथवा बाइबल सभी में दया को ईश्वर को पाने का माध्यम बताया गया है। ईश्वर को फूल, फल अथवा मंत्र से ध्यान करने का उद्देश्य भी यही है कि हमारा मन निर्मल हो और मन में दया की भावना बढ़े। जिसने दया करना सीख लिया वह ईश्वर का पुत्र हो जाता है।

परमात्मा के समकक्ष

ईसा मसीह, भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, साईं सभी ने अपने जीवन में दया का अनुपम परिचय दिया। अपने इसी गुण के कारण ईश्वर ने इन्हें प्यार किया और ईश्वरीय शक्ति इनमें समाहित हो गयी।

यस्य चित्तं द्रवीभूतं कृपया सर्वजंतुषु।
तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किं जटाभस्मलेपनैः।।

अर्थात जिसका हृदय सभी प्राणियों पर दया करने हेतु द्रवित हो उठता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, जटा और भस्म लगाने की क्या जरूरत? भाव यह है कि हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, उनसे स्नेह करना चाहिए। जो ऐसा करता है, उसका स्थान परमात्मा के समकक्ष हो जाता है।

दया धर्म का मूल

किसी अन्य प्राणी को कष्ट में देखने पर उसके कष्ट दूर करने के उद्देश्य से उसकी सहायता करने की जिस इच्छा का मनुष्य के हृदय में जन्म होता है, वह दया या करुणा कहलाती है। गोस्वामी तुलसी दास जी ने राम चरित मानस में एक दोहे में कहा है-दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िये जब लगि घट में प्राण।।

विचारणीय यह है कि यदि दया धर्म का मूल है तब धर्म को स्थायित्व प्रदान करने और सशक्त बनाये जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, जो धर्म में विश्वास रखता है अथवा जो धर्म की उन्नति चाहता है अथवा जो अपने को धर्म का रक्षक कहता है, को अपने अन्दर के दया भाव को जागृत कर उसका प्रयोग धर्म की जड़ों के सशक्तिकरण के लिए करना होगा। सभी प्राणियों पर दया करते हुए असहाय दलितों, वंचितों और गरीबों पर विशेष दया दृष्टि से उनका दर्द कम करना होगा। कोरे भाषण देकर धर्म की पैरवी करने, दयनीय जीवन जी रहे लोगों को अल्पकालिक लालच देकर अपने समुदाय में शामिल करने अथवा उनके इर्द-गिर्द पहरेदार खड़े करने से धर्म की जड़ें मजबूत नहीं होंगी।

जीवन के प्रति सजग भाव

जिस मनुष्य में जीवन के प्रति सहज भाव है उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संत रविदास ने कहा है कि 'मन चंगा तो कठौती में गंगा'। इसके विपरीत बाजार के आर्थिक स्वामी तथा प्रचार प्रबंधक अपने शोर से लोगों के मन को ही भटकाते हैं। जिस धर्म का पालन सही ढंग से एकांत में हो सकता है उसे उन्होंने चौराहे पर चर्चा का विषय बना दिया है। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में यही स्थिति है। हर धर्म के ठेकेदार अपने निर्धारित विशिष्ट रंगों के वस्त्र पहनकर यह प्रमाणित करते हैं कि वह अपने समाज के माननीय हैं। यह अलग बात है कि किसी भी धर्म के मूल प्रवर्तक ने अपने समाज के लिए किसी खास रंग की पहचान नहीं बनाई। इस तरह धर्म को लेकर एक तरह से भ्रम की स्थिति बन गई है। अगर हम प्राचीन ग्रंथों के आधार पर धर्म के सिद्धांत की पहचान करें तो वह आचरण के आधार पर बना हुआ होता है। उसका कोई निश्चित कर्मकांड नहीं है। यही कारण है कि धार्मिक रूप से हमारे यहां एकता है पर कर्मकांडों में स्थान और क्षेत्र के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। जहां तक स्वयं धर्म के आधार पर चलने का प्रश्न है तो उस पर अवश्य विचार करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर योगसाधना तथा पूजा आदि कर मन को स्वस्थ तथा प्रसन्न चित्त बनाना चाहिए। उससे पूरा दिन अच्छा निकलता है। धर्म को लेकर लोगों से अधिक चर्चा नहीं करना चाहिए क्योंकि अधिकतर लोग इस बारे में अपना ज्ञान बघारते हैं। हमारे आसपास धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग उंगलियों पर गिनती करने लायक ही होते हैं।

कलिंग समाचार

संपादकीय

रविवार 18 जनवरी 2026

मोदी के हाथ में त्रिशूल और डमरू

गले में भगवा गमछा, माथे पर त्रिपुंड और हाथों में भगवान शिव की तरह त्रिशूल और डमरू पकड़े हुए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नया अवतार सामने आया है। अलग–अलग विचारधारा और कार्यशैली के प्रधानमंत्री देश ने देखे हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री को देश देख रहा है, जिनकी वक्त–वक्त पर बदलती वेशभूषा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की याद दिलाती है। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी कोई भी काम अकारण नहीं करते। इस बार हिंदुत्व का जयघोष करने वाली मुद्रा उन्होंने सोमनाथ में 8 से 11 जनवरी तक आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए धारण की। इस उत्सव को भव्य बनाने में गुजरात की भाजपा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि इसके गहरे राजनैतिक निहितार्थ भी हैं। एक हजार साल पहले1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला हुआ था। उसी याद में यह उत्सव मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चन्द्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। लोककथाओं के अनुसार यहीं श्रीकृष्ण ने देहत्याग किया था। यह ऐतिहासिक मंदिर अब भाजपा के लिए राजनैतिक महत्व का भी बन गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के अनुसार, यह उत्सव विनाश को याद करते हुए नहीं बल्कि आस्था, सांस्कृतिक आत्मस मान और पुनर्जन्म की भावना के स मान के रूप में मनाया जा रहा है। दरअसल प्राचीन सोमनाथ मंदिर में कई गांवों का चढ़ावा आता था, जिससे यहां सोने, चांदी, बड़ी सं या में मोतियों और अनमोल रत्नों समेत बड़ी धनसंपदा सदियों से जमा थी और इस वजह से विदेशी हमलावर इसे लूटना चाहते थे। महमूद गजनी ने 1026 में जब भारत पर एक और आक्रमण किया तो उस समय गुजरात में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम का शासन था, महमूद गजनी ने तभी सोमनाथ पर पहला आक्रमण किया था। इसके बाद कई और शासकों और आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर हमले किए और इसकी धन संपदा को लूटा। मध्ययुग का वह दौर ऐसा ही था, जिसमें राज्य और शक्ति बढ़ाने के लिए शासक खुलेआम लूटपाट करते थे। अभी अमेरिका इसी तरह के काम कर रहा है, बस इसमें लोकतंत्र का आवरण ओढ़ लिया है और सीधे–सीधे गैर धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। खैर, सोमनाथ पर कम से कम 16 बार आक्रमण और देश के दूसरे हिंदू धर्मस्थानों पर हुए आक्रमण के बावजूद देश से न हिंदू धर्म खत्म हुआ, न हिंदुओं के अस्तित्व पर कोई खतरा आया। लेकिन मोदीराज में आस्था के पुनर्जन्म के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करके सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। सोमनाथ पर भाजपा पहले भी सफल दांव खेल चुकी है। दिसंबर 1989 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने पहली बार अपने चुनावी घोषणापत्र में राम मंदिर (अयोध्या) निर्माण के मुद्दे को शामिल किया था। तब उसकी लोकसभा सीटें बढ़ीं, फिर 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा शुरू की, जिसके बाद भारत में वही धार्मिक विभेद की खाई गहरी होनी शुरु हुई, जो भाजपा की सत्ता के लिए जरूरी थी। 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। फिर 1996 में भाजपा को केंद्र की सत्ता में आने का मौका पहली बार मिला। और अब नरेन्द्र मोदी के आने के बाद तो 12 सालों से भाजपा के पास सत्ता है। ध्यान रहे कि आडवाणी की रथयात्रा में गुजरात में नरेन्द्र मोदी को बड़ी जि मेदारी दी गई थी, जिसे मोदी ने सफलतापूर्वक निभाया। सवाल भाजपा को सत्ता में लाने का था, तो नरेन्द्र मोदी ने पूरी तैयारी से अपनी जि मेदारी निभाई। लेकिन अभी प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद मोदी लगातार अपने पद की गरिमा निभाने में नाकाम दिख रहे हैं। इंदौर में कई लोग दूषित पेयजल से मर गए, मोदी ने उफ तक नहीं की। दिल्ली से लेकर कई शहरों में हवा जानलेवा बनी हुई है। उन्नाव की पीड़िता इंसाफ के लिए लड़ती रही, मोदी चुपचाप देखते रहे। अभी अंकिता भंडारी मामले में लोगों ने आक्रोश न दिखाया होता तो भाजपा सरकार बेफिक्र बैठी रहती। उत्तरप्रदेश में लगातार महिला उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं।

मुस्लिम सावधान:ओवैसी बंगाल में हिजाबी मुख्यमंत्री का शिगूफा छेड़ सकते हैं!

शकील अख्तर

देश में जहां अभी केन्द्र सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री तक नहीं है वहां हिजाबी महिला के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाने की बात करना सिवाय जज्बात भड़काने के और क्या है? मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के बहुत सारे काम होना है। प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही बनेगी लेकिन नौकरी पाकर बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं मजबूत होंगी। महिला शिक्षा महिलाओं के आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने पर ओवैसी कभी बात नहीं करते हैं। असदउद्दीन ओवैसी को बड़ा बैरिस्टर कहकर उनका महिमामंडन किया जाता है। लेकिन एक सामान्य वकील भी जानता है कि उन्हें किसी ऐसे तर्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो उसके क्लाइंट के लिए ही उल्टा पड़ सकता हो। एक बार नहीं दूसरी बार फिर ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी।

भारत का प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। संविधान कहता है। मगर अभी तक कोई दलित भी नहीं बन सका है। अपने व्यक्तिगत करिश्मे के दम पर मायावती को यह मौका मिल सकता था। मगर डर की राजनीति की वजह से उन्होंने यह गंवा दिया। बड़ी पार्टियों में से भाजपा अपनी मनुवादी सोच के कारण कभी किसी दलित को यह मौका नहीं दे सकती है। उसकी तो आरक्षण और उस संविधान को भी जिसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है खत्म करने की मंशा है। मगर मौका नहीं मिल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी चार सौ पार मांगे थे मगर अभी थोड़ा होश में बची जनता और विपक्ष के एकजुट होकर चुनाव लड़ने की वजह से उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। वहां दलित प्रधानमंत्री की बात कोई सोच भी नहीं सकता। संघ की और बीजेपी की पूरी राजनीति सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरोध में है। वापस पुरानी व्यवस्था बनाना। जिसे वह समरसता कहती है। यह शब्द संघ का ही गढ़ा हुआ है। मगर जानकारी के अभाव में कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेता, लेखक पत्रकार भी इस शब्द का उपयोग सामाजिक न्याय के संदर्भ में करते रहते हैं। जबकि यह शब्द कहता है कि दलित पिछड़ों को स्थापित समाज के साथ समरस रहना चाहिए। मतलब उनके अनुसार बनी हुई सामाजिक व्यवस्था में।

दलित नेता रामदास अठावले यह जानते हैं। मोदी के साथ रहने के बावजूद उन्होंने पत्र लिखकर उनसे कहा था कि सरकारी कागजों में सामाजिक न्याय के बदले इस शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसे बंद होना चाहिए। जाहिर है कि उनकी इस बात को किसी को सुनना नहीं था। मगर संतोष की बात है कि कुछ दलित नेता संघ की इन बारीक कारगुजारियों को समझते हैं। कुछ कर नहीं पाएं वह अलग बात है। ज़्यादा जानें बॉलीवुड समाचार खेल उपकरण बजट 2019 युवा मनोरंजन विविध समाचार हिंदी समाचार ऐप सदस्यता राजनीति समाचार बॉलीवुड समाचार पत्रिका साक्षात्कार कौशल प्रशिक्षण समाचार सदस्यता तो दलित जिसे वे हिन्दुत्ववादी राजनीति में शामिल मानते हैं उसे वे देश के सर्वोच्च पद की लिए स्वीकार नहीं कर सकते तो मुस्लिम का नाम जिसके खिलाफ उनकी पूरी राजनीति है उसकी हिजाबी महिला का नाम आना तो उनकी ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए और फायदेमंद ही है।

ओवैसी यह काम कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि बीजेपी की हिन्दू–मुस्लिम राजनीति कमजोर पड़ गई है। तो उसे वापस मजबूत करने के लिए ओवैसी ने अपने इस बयान को फिर दोहरा दिया। इससे पहले वे कर्नाटक में इस विषय पर हुए विवाद के बाद यही बात कि हिजाबी लड़की एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी कह चुके थे। ओवैसी मुस्लिम की राजनीति करते हैं। और इस के लिए वे सबसे बड़ा मुद्दा यह उठाते हैं कि मुस्लिम का नेता मुस्लिम ही हो सकता है। वे मुस्लिम कयादत की बात करते हैं। यह बात तो बीजेपी को बहुत सूट करती है। 15– 16 प्रतिशत मुस्लिम का नेता मुस्लिम तो बाकी हिन्दुओं का नेता हिन्दू। तो उनकी मुस्लिम कयादत की राजनीति में देश का बहुसं यक गैर मुस्लिम हिजाबी महिला प्रधानमंत्री को कैसे स्वीकार कर लेगा?

देश में जहां अभी केन्द्र सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री तक नहीं है वहां हिजाबी महिला के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाने की बात करना सिवाय जज्बात भड़काने के और क्या है? मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के बहुत सारे काम होना है। प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही बनेगी लेकिन नौकरी पाकर बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं मजबूत होंगी। महिला शिक्षा महिलाओं के आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने पर ओवैसी कभी बात नहीं करते हैं।

बस बैरिस्टर साहब हिजाबी महिला के प्रधानमंत्री बनने की बात हर उस समय दोहरा देते हैं जब बीजेपी को सा प्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए उसकी जरूरत होती है। यह बैरिस्टर विपक्षी को अपने क्लाइंट (मुस्लिम जिसके वे कायद,नेता होने का दावा करते हैं) पर और ज्यादा हमले करने का मौका मुहैया करवाते हैं। बंगाल में चुनाव हैं। बीजेपी को मुस्लिम वोट काटने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी ओवैसी ही हो सकते हैं। इस तरह के जज्बात भड़काकर वे मुस्लिम वोट काटते हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है।

अभी बिहार में सबसे देख लिया। ओवैसी ने बीजेपी के सा प्रादायिक ध्रुवीकरण का साथ देकर उसके अब तक के सर्वाधिक 89 विधायकों को चुनाव जितवा दिया और खुद भी सबसे ज्यादा 5 मुस्लिम विधायक जितवा लिए। लेकिन नुकसान क्या हुआ? 243 सीटों में से मुस्लिम विधायकों की सं या केवल 11 रह गई। जबकि पिछली बार 2020 में 19 थी। और 2015 में 24। ओवैसी की खुद की सीटें आ जाती हैं और बाकी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की सीटें भी कम हो जाती हैं और उनसे लड़ने वाले मुस्लिम प्रत्याशी भी हार जाते हैं। ज़्यादा जानें खेल उपकरण संपादकीय लेख युवा मनोरंजन साक्षात्कार संग्रह विविध समाचार बजट 2019 मनोरंजन पत्रिका प्रमुख समाचार हिंदी समाचार ऐप सदस्यता ई–पेपर सदस्यता बंगाल में इस बार बीजेपी हर दांव आजमा रही है। ममता बनर्जी के लिए हर फ्रंट पर मुश्किलें खड़ी कर रही है। ईडी की एंट्री करवा दी है। एसआईआर चल ही रहा है। और धार्मिक विभाजन के लिए वहां बाबरी मस्जिद बनवाने और हिजाबी महिला के प्रधानमंत्री बनने की जज्बाती राजनीति की शुरूआत करवा दी गई है। बिहार में तो केवल 18 प्रतिशत ही मुस्लिम वोट थे। बंगाल में इससे लगभग दो गुने हैं। वहां इस समय 44 मुस्लिम विधायक हैं। मगर इससे बहुत ज्यादा सं या में वहां मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष दलों को जिनमें इस समय वहां टीएमसी ही प्रमुख है, चुनाव जितवाता है। हुमायूं कबीर जो वहां बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और ओवैसी जो अभी तो हिजाबी मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं चुनाव आने तक कोई आश्चर्य नहीं करना कि वे बंगाल में हिजाबी मु यमंत्री की बात न करने लगें।

प्रधानमंत्री दूर की चीज है। बंगाल में महिला मु यमंत्री हैं तो यहां हिजाबी मु यमंत्री का नारा ज्यादा चलेगा! सावधान ममता को या दूसरे धर्मनिरपेक्ष दलों को नहीं रहना है। वे तो अपने सिद्धांतों पर रहेंगे होशियार मुस्लिम को रहना होगा। जिन्ना की इसी तरह की राजनीति ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। और जो पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया वह पूरी तरह एक फेल्ड स्टेट (असफल राष्ट्र) में तबदील हो चुका है। तरक्की के मामले में वह भारत के मुकाबले कहीं नहीं है। भारत का मुसलमान हमेशा से धर्मनिरपेक्ष नेताओं को ही अपना नेता मानता रहा है। पहले नेहरू को माना फिर मुलायम, लालू, ममता बनर्जी जैसे क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ भी गया। लेकिन अब ओवैसी नया शिगुफा लाए हैं। मुसलमानों को अपनी कयादत खड़ी करना होगी। 15–16 प्रतिशत आबादी अपनी कयादत खड़ी करके क्या करेगी? वही हाल होगा जो अभी बिहार में हुआ। न कयादत खड़ी होगी न दूसरे धर्मनिरपेक्ष दल जीत पाएंगे। न खुदा ही मिला न विसाले सनम वाली हालत हो जाएगी। बंगाल के साथ अभी असम और केरल में भी चुनाव हैं। वहां भी बंगाल की तरह मुस्लिम विधायकों की सं या अच्छी खासी है। दोनों जगह 32–32 विधायक हैं। इनके साथ तमिलनाडु में भी चुनाव हैं वहां 6 हैं। और पुडुचेरी में एक। हवा सब जगह एक साथ चलेगी। मीडिया इसे और बढ़ाएगा। रोकना केवल मुस्लिम के हाथ में है। जज्बातों में नहीं बहना। जो इशु बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी शिक्षा, सरकारी चिकित्सा उसके हिन्दू भाइयों के हैं वही उसके भी। हिजाबी प्रधानमंत्री और हिजाबी मु यमंत्री कोई इशु नहीं हैं। यह जबर्दस्ती बनाया जा रहा इशु है। भावनाओं को भड़काने के लिए। ज़्यादा जानें संपादकीय लेख ताज़ा समाचार मु य शीर्षक ताज़ा खबरें अपडेट प्रादेशिक समाचार राजनीति समाचार हिंदी भाषा शिक्षण डिजिटल मार्केटिंग सेवाएँ बजट संबंधित वित्तीय सेवाएँ साक्षात्कार संग्रह मुस्लिम को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। भाजपा की हिन्दू–मुस्लिम राजनीति को अब हिन्दू नकार रहा है। बहुत नुकसान उठा लिया उसने। सरकारी नौकरी खत्म हो गई। उसके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए अब दांव मुस्लिम पर लगाया जा रहा है कि वह जज्बाती इशु को हवा देगा ताकि फिर हिन्दुओं को भी उसी लाइन पर वापस लाया जाए। सा प्रदायिक राजनीति खत्म होना हिन्दू मुसलमान दोनों के हित में है।

देश के लिए फायदेमंद है चाइल्ड केयर में निवेश करना

डॉ. पवित्र मोहन

एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) की पालना योजना के तहत परिकल्पित राज्य प्रायोजित डे–केयर सेंटर में बड़ी संभावनाएं हैं लेकिन वे वर्तमान में महत्वाकांक्षा न होने और कम बजटीय आवंटन से विवश होने से ग्रस्त हैं। मजबूत परिवारों को मजबूत सहायक संरचनाओं की आवश्यकता होगी। समाज और राज्य की जि मेदारी है कि वे इन्हें स मान के साथ प्रदान करें। फ़ैमिली गेम न्यूयार्क में मेयर का चुनाव जीतने वाले जोहरान ममदानी की जीत का एक बड़ा कारण शहर के सभी बच्चों के लिए राज्य प्रायोजित चाइल्ड केयर की गारंटी देना था। लोक कल्याण पर खर्च न करने की नीति रखने वाले, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्र प के समय और अमेरिका में दूर–दक्षिणपंथ की नई और यहां तक कि अंधी दिशा में जा रहे देश में यह एक साहसिक वादा था। ममदानी की जीत इंगित करती है कि अमेरिकी मतदाता साहसिक विचारों के साथ काम करते हुए समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं। भारत के संदर्भ में बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक बड़ी चुनौती को देखते हुए इस विषय पर गंभीर चर्चा हो सकती है कि कैसे और क्यों बच्चों पर केंद्रित जमीनी स्तर के विकास का एजेंडा विभिन्न दलों के राजनीतिक एजेंडे में वरीयता प्राप्त कर सकता है।

बच्चों को हर जगह एक सुरक्षित, सहायक व पोषण करने वाले वातावरण की आवश्यकता होती है। आधुनिक दुनिया और इसकी अर्थव्यवस्था ने सामाजिक–आर्थिक स्तर पर बच्चों की देखभाल करने के लिए परिवारों की क्षमता को सीमित कर दिया है। छोटे परिवार के आकार, माता–पिता दोनों को घर से बाहर काम करने की आवश्यकता, लंबे समय तक काम के घंटे, लोगों को काम के लिए बाहर जाने की जरूरत; इन सभी मुद्दों ने अपने बच्चों की देखभाल करने की परिवारों की क्षमता को कम कर दिया है।

हालांकि अमीर परिवार निजी चाइल्ड केयर का खर्च उठा सकते हैं और उनके बच्चे घर पर या संस्थानों में बढ़ते रहते हैं, परन्तु गरीब परिवारों में बच्चे समुचित चाइल्ड केयर के बिना बढ़ते हैं जो अक्सर उनकी वृद्धि, विकास और भावनात्मक क्षमता को अत्यंत सीमित कर देते हैं। आमतौर पर किसी भी देखभाल करने वाले की अनुपस्थिति में उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य से भी समझौता किया जाता है। यह देखा गया है कि ग्रामीण भारत, विशेष रूप से ग्रामीण राजस्थान के कई हिस्सों में पुरुष श्रम–रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं जबकि महिलाएं और बच्चे अक्सर पीछे रह जाते हैं। महिलाएं जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने, पानी लाने, खेतों में काम करने और बुजुर्गों की देखभाल करने का काम करती हैं। उनके पास खुद की या अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए समय नहीं होता। अधिकतर ऐसा होता है कि छोटे बच्चे खुद अपनी देखभाल करते हैं या उनका कोई बड़ा भाई–बहन उनकी देखभाल करता है जो अक्सर खुद ही एक छोटा बच्चा होता है। कभी–कभी दादा–दादी को बच्चों की देख–भाल करने का जि मा दिया जाता है पर ज्यादातर मामलों में वे स्वयं अपनी शारीरिक स्थितियों के कारण असमर्थ होते हैं। फलतः कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कभी बच्चे कुओं में गिर जाते हैं या जानवरों द्वारा रौंद दिए जाते हैं अथवा अकेलेपन का शिकार हो कर निष्क्रिय पड़े रहते हैं।

राजस्थान की कई बस्तियों में जहां डे–केयर सेंटर चलाये हैं, उनमें देखा गया है कि ऐसे केंद्रों में रखे गए अधिकांश बच्चे अच्छी तरह से विकसित होते हैं और स्कूलों में उन बच्चों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं जिन्हें खुद के हाल पर छोड़ दिया जाता है। उनकी माताओं ने यह भी बताया कि जब वे काम के लिए जाती हैं तो अपने बच्चों की भलाई के बारे में उन्हें बहुत कम चिंता रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे खुद के आराम के लिए कुछ समय भी निकाल लेती हैं। शहरी अहमदाबाद में कई प्रवासी परिवार निर्माण स्थलों पर काम करते हैं जहां बच्चों को अक्सर इधर–उधर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे उन्हें चोट लगने, उनके उपेक्षित रह जाने और कुपोषण का बहुत खतरा होता है। इन स्थलों पर गैर–सरकारी संगठनों और नियोक्ताओं द्वारा प्रबंधित डे–केयर सेंटर इन परिवारों के बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा और पोषण प्रदान करते हैं।

इन स्थितियों में बाल देख–भाल सीमित परिस्थितियों में की जाती है जो सरकार की मदद के बिना संचालित होती है और वह एक अधिकार नहीं होता। यह देखते हुए कि विकास के लिए बच्चों के प्रारंभिक वर्ष मूलभूत हैं और परिणामों को आजीवन आकार देते हैं, न्यूनतम निवेश से होने वाले भारी लाभों को देखते हुए और अधिक क्षेत्रों तथा राज्यों में बाल देख–भाल मॉडल का विस्तार करने की आवश्यकता है। इस बारे में किए गये कई अध्ययन इसका समर्थन करते हैं। जर्नल ऑफ ग्लोबल हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार नि न और मध्यम आय वाले देशों में 0–3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए केंद्र–आधारित चाइल्ड केयर पर अध्ययनों की एक प्रणालीगत समीक्षा बच्चों के विकास, पोषण और विकास मेट्रिक्स में सकारात्मक परिणामों से जुड़ी है। 2011 की एक लैंसेट समीक्षा में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि चूंकि बच्चों का विकास हो रहा होता है तो बढ़ते केंद्र–आधारित प्रारंभिक शिक्षण कार्यक्रम बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, स्कूल की तैयारी में सुधार करते हैं और मजबूत शैक्षणिक प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। हाशिए में रहने वाले बच्चों के लिए ये लाभ अधिक गहन होते हैं। वैश्विक साक्ष्य से पता चलता है कि संज्ञानात्मक कामकाज और सामाजिक–भावनात्मक कौशल का निर्माण बेहतर शिक्षा, रोजगार तथा वयस्क होने पर कमाई में बदल जाता है। यह गरीबी के अंतर–पीढ़ीगत चक्र को तोड़ने में मददगार होता है। जमैका से एक ऐतिहासिक अध्ययन (गर्टलर, पॉल, एट अल %लेबर मार्केट रिटर्न्स टू एन अर्ली चाईल्डहुड स्टिमुलेशन इंटरवेन्शन इन जमैका%, साईंस– 2014) ने पाया कि जिन बच्चों को पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, उन्होंने 20 साल बाद उन लोगों की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक आय अर्जित की जिन्हें ऐसे अवसर और सुविधाएं नहीं मिली थीं। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए अकाट्य सबूत हैं कि कम और मध्यम आय वाले देशों में भी बड़ी सं या में माताओं को काम करने में सक्षम बनाने में चाइल्ड केयर की उपलब्धता किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैसे–जैसे अधिक सं या में माताएं कार्यबल में शामिल होती हैं, समग्र रोजगार दर बढ़ती है। इकानॉमिस्ट इ पैक्ट के चाइल्ड केयर डिविडेंड इनिशिएटिव (%ब्रिजिंग द एक्सेस गैप% क्रांटिफाइंग द इकोनॉमिक रिटर्न ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन चाइल्ड केयर%) द्वारा किए शोध का अनुमान है कि चाइल्ड केयर सेवाओं तक पहुंच गुणक प्रभाव के माध्यम से हर साल राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 1 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि नि न और मध्यम आय वाले देशों में कार्यबल में माताओं की कम भागीदारी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। महिलाओं के लिए यह कीमत व्यक्तिगत और वित्तीय दोनों हैं। यह न केवल कैरियर के विकास को धीमा और कमाई को कम करता है बल्कि उनकी स्वतंत्रता तथा काम देने वाली एजेंसी की क्षमता को भी कम करता है। कम मातृ श्रम शक्ति भागीदारी दर के कारण घरेलू आय नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास कम होता है। द इकानॉमिस्ट की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि अपर्याप्त चाइल्ड केयर कितना महंगा हो सकता है– नाइजीरिया में लगभग पांच में से एक बच्चा स्कूल जाने की उम्र से कम का है और अधिकांश छोटे बच्चों की देखभाल घर पर की जाती है। वहां 2022 में महिलाओं की काम करने की सीमित क्षमता के कारण देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1.09 प्रतिशत आय का नुकसान हुआ। चाइल्ड केयर उद्योग में सृजित नौकरियों के कारण आर्थिक लाभ भी उत्पन्न होते हैं।

विविध समाचार

गुरदासपुर में छुट्टी के दिन खुला स्कूल, 5 फीट तक घुसा पानी, 400 के करीब छात्र और अध्यापक फंसे

गुरदासपुर १७/०१ (संवाददाता): पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के कहर के बीच एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। पंजाब सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के बावजूद दीनानगर के सीमावर्ती गांव दबूड़ी में नवोदय विद्यालय खोला गया, जिसके चलते स्कूल में करीब 400 छात्र और कई अध्यापक बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 27 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक छुट्टियों का ऐलान किया था। लेकिन इन आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए दीनानगर के नवोदय विद्यालय प्रशासन ने आज स्कूल खोल दिया। नतीजा यह हुआ कि स्कूल में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया और छात्र व अध्यापक स्कूल परिसर के अंदर ही फंसकर रह गए। जब इस गंभीर लापरवाही के बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से सवाल किया गया, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने माना कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा आज से छुट्टियों का ऐलान किया गया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि स्कूल में पानी बीती रात से ही घुसना शुरू हो गया था। यह बयान प्रिंसिपल की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है कि खतरे का अंदेशा होने के बावजूद स्कूल क्यों खोला गया। फिलहाल, प्रिंसिपल का कहना है कि सभी छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित स्कूल भवन की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया गया है। स्कूल प्रशासन अब जिला प्रशासन से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। इस घटना ने स्कूल प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनकी एक बड़ी गलती के कारण आज 400 बच्चों और शिक्षकों की जान खतरे में पड़ गई है।

पंजाब के स्कूलों में बच्चों को जल्द मिलेगा ब्रेकफास्ट, सीएम मान बोले– कैबिनेट में लाएंगे प्रस्ताव

चंडीगढ १७/०१ (संवाददाता): तमिलनाडु दौरे पर गए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 'ब्रेकफास्ट स्कीम' शुरू की जाएगी। सीएम मान ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ मिलकर शहरी प्राथमिक स्कूलों में चल रही ब्रेकफास्ट स्कीम का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों को भोजन परोसा और उनके साथ बैठकर नाश्ता भी किया। मान ने कहा कि पंजाब सरकार इस योजना को लागू करने पर कैबिनेट में चर्चा करेगी। उनका कहना था कि इससे बच्चों की पोषण स्थिति और शिक्षा दोनों को लाभ होगा। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। मान ने कहा कि "देश में नेता जुमलेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। सच ही हमेशा आगे चलता है, भाषणों से देश नहीं बनता।" मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है और राज्य में अनाज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तमिलनाडु का खाना राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो चुका है। पंजाब के हर कस्बे में मसाला डोसा, उपमा और पानीपुरी आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि, पंजाबी खाना थोड़ा भारी माना जाता है।

हरियाणा में केवल कानून की चलेगी हुकूमत : नायब सिंह सैनी

चंडीगढ १७/०१ (संवाददाता): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। इस नीति की घोषणा उन्होंने 18 अक्टूबर, 2024 को प्रथम मंत्रिमंडल बैठक के बाद ही कर दी थी। उस समय मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अपराधी या तो अपने रास्ते बदल लें अन्यथा सरकार उन्हें सुधारने के लिए बाध्य करेगी। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत या प्रभावशाली पद के बावजूद, यदि वह कानून तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में कानून की सर्वोच्चता स्थापित होगी, अपराधी की हैसियत नहीं। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विपक्ष द्वारा प्रदेश की कानून–व्यवस्था को लेकर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी स्पष्ट चेतावनी का ही परिणाम है कि आज हरियाणा में प्रमुख अपराधों की संख्या और दर दोनों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्ष 2014 से पूर्व की स्थिति के विपरीत आज न तो नागरिक को एफआईआर दर्ज करवाने में कोई बाधा आती है और न ही पुलिसकर्मी को अपराधियों पर कार्रवाई करने से भयभीत होना पड़ता है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के कारण आज प्रदेश की जनता का हरियाणा पुलिस पर भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है। विपक्ष पर बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल (2004–2014) में बलात्कार की घटनाएं तीन गुना बढ़ीं। वर्ष 2004 में ऐसे 386 मामले दर्ज हुए थे, जो 2014 में बढकर 1174 तक पहुँच गए। उन्होंने विपक्ष को असंवेदनशील सरकार बताते हुए कहा कि दस वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस ने मात्र एक ही महिला थाना, खानपुर कलां में खोला। कांग्रेस शासन के दौरान घटित एक मामले का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 अप्रैल, 2008 को रोहतक थाना परिसर में ही 5 पुलिसकर्मियों ने एक महिला के साथ बलात्कार किया। पीडिघ्ता 40 दिनों तक न्याय

के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मात्र 8 माह में, 15 मई 2025 को, अदालत से उसे फांसी की सजा सुनाई । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री की दूरदर्शी सोच से ही अंग्रेजों के बनाए पुराने कानूनों को हटाकर नए और कार्रवाई के लिए दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर काटती रही, लेकिन न तो पुलिस ने उसकी सुनी और न ही उस समय के किसी विधायक, सांसद या मंत्री ने मदद की। अंततः जब मामला लगातार मीडिया की सुर्खियाँ बना तो 31 मई, 2008 को एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद भी पीडिघ्ता को इतनी प्रताडना झेलनी पड़ी कि 9 जून, 2008 को उसने पंचकूला में पुलिस मुख्यालय के बाहर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मामले में हडकंप मचने पर कांग्रेस सरकार ने 16 जून, 2008 को केस सीबीआई को सौंपा। पाँच वर्ष बाद 20 जुलाई, 2013 को सीबीआई अदालत ने एक सब इंस्पेक्टर और एक हेडकांस्टेबल को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। इसके विपरीत, मौजूदा सरकार की त्वरित कार्रवाई का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 सितंबर, 2024 को जिला यमुनानगर में एक नाबालिग आपराधिक कानून लागू किए गए, जिनकी वजह से यह संभव हुआ। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि 2004 से 2014 तक के अपने शासनकाल में यदि किसी बलात्कारी को उन्होंने फांसी की सजा दिलवाई हो तो उदाहरण प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि मौजूदा कार्यकाल में अनेक मामलों में 7–8 महीनों के भीतर ही दोषियों को 20–20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास अथवा फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे स्पष्ट है कि डबल इंजन सरकार ने अपराधियों पर प्रभावी नकेल कसी है। इनेलो के एक पूर्व विधायक पर मई 2011 में रोहतक जिले के कलानौर अनाज मंडी में गोलीबारी कर हत्या का आरोप लगा था। घटना के बाद आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने पैतृक गांव मोखरा को समर्थकों की मदद से किले में बदल दिया। हथियारबंद समर्थकों की घेराबंदी के कारण पुलिस भीतर नहीं जा पाई। अंततः आरोपी ने जुलूस निकालकर आईजीपी कार्यालय पहुँचकर आत्मसमर्पण किया। 2013 में हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। रोहतक के बहुचर्चित अपना घर कांड का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मई 2012 में यह जघन्य अपराध हुआ, जिसमें अनाथालय की बच्चियों पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। 8 मई, 2012 को राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की टीम ने छापा मारकर लगभग 120 बच्चियों को मुक्त कराया। जून 2012 में यह केस सीबीआई को सौंपा गया। अप्रैल 2018 में सीबीआई की विशेष अदालत ने मुख्य संचालिका जसवंती देवी और उसके दामाद जयभगवान सहित 9 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजाएं सुनाईं। कांग्रेस कार्यकाल की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 जून, 2008 को एक प्रमुख हिंदी अखबार ने "लंबी है हरियाणा पुलिस के कारनामों की फेहरिस्त" शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें 1996 से 2008 तक पुलिस अधिकारियों के दुराचार, रिश्वतखोरी और अपराधों का विवरण था। उन्होंने इस उदाहरण से विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया।

भारी बारिश से पंजाब के 7 जिलों में बाढ़, पठानकोट–जालंधर रेलवे रूट बंद, 90 ट्रेनें प्रभावित

चंडीगढ १७/०१ (संवाददाता): पंजाब, हिमाचल और जम्मू–कश्मीर में जोरदार बारिश होने के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण रणजीत सागर डैम और भाखड़ा डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है जिस कारण रावी, सतलुज और ब्यास नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं, भारी वर्षा के कारण पठानकोट में चक्की पुल को नुकसान हुआ है। ब्यास नदी पर बने इस पुल के नीचे से मिट्टी धंसने के कारण रेलवे की जम्मू डिविजन ने जम्मू–जालंधर रेल ट्रैक को बंद कर दिया है। इस कारण करीब 90 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कुछ ट्रेनों को पठानकोट– अमृतसर, जालंधर रूट से रवाना किया जा रहा है। फिलहाल रेलवे ने चक्की पुल से ट्रेनों की आवाजाही अगले आदेश तक बंद कर दी है। पंजाब में 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्थिति गंभीर होते देख जालंधर, कपूरथला, पठानकोट और गुरदासपुर जिलों के साथ–साथ अमृतसर के अजनाला और रईया ब्लॉक के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है।

वहीं फाजिल्का के बाढ़ग्रस्त 20 गांवों के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। तरनतारन और फिरोजपुर में हरिके हेडवर्क्स से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सुल्तानपुर लोधी के गांव अहली कलां में ब्यास नदी के धुसी बांध में दरार आ गई। जिल कारण किसानों की फसलें तबाह हो गई है।

पीएसपीसीएल के नार्थ जोन के नए चीफ इंजीनियर देस राज बांगर ने पदभार संभाला

जालंधर १७/०१ (संवाददाता): संतुष्टि ही हमारा प्रथम ध्येय है। इस अवसर पीएसपीसीएल के नार्थ जोन के नए चीफ पर डिप्टी चीफ इंजीनियर गुलशन चुटानी, वेस्ट इंजीनियर देस राज बांगर ने पदभार संभाल डिवीजन के अडीशनल एसई इंजीनीयर सन्नी लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली भागरा, ईस्ट डिवीजन के एडीशनल एसई सप्लाई को सुचारू रखा जाएगा और बारिश के इंजीनियर जसपाल सिंह, कैंट डिवीजन के कारण अगर समस्या आती है तो उसे प्राथमिकता एडीशनल एसई इंजीनियर अवतार चंद और के आधार पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा माडल टाऊन डिवीजन के सीनियर एक्सईएन कि पीएसपीसीएल बिजली उपभोक्ताओं की जसपाल सिंह पाल ने नए चीफ इंजीनियर देस सेवा में कार्य कर रहा है और उपभोक्ताओं की राज बांगर को बुके देकर उनका स्वागत किया।

भारत में आजादी सिर्फ एक राजनीतिक अवधारणा

चण्डीगढ़। लोकतंत्र और आजादी सुनिश्चित करने के तमाम आधुनिक उपकरणों, जैसे संविधान आधारित शासन व्यवस्था, न्यायपालिका, मीडिया, तकनीक, नागरिक समाज आदि ने सचमुच लोकतंत्र और आजादी की रक्षा की है या इनके उज़रोज़र क्षरण का रास्ता बनाया है? यह एक जटिल सवाल है। एक समय 18वीं सदी के मध्य में महान दार्शनिक ज्यां जॉक रूसो के सामने सवाल था कि आधुनिक विज्ञान और कलाओं ने मनुष्य को बेहतर बनाया है या नैतिक रूप से भ्रष्ट बनाया है? रूसो का जवाब था कि आधुनिक कला और विज्ञान ने मनुष्य को नैतिक रूप से भ्रष्ट बनाया है। रूसो के निष्कर्ष के पौने तीन सौ साल और भारत की आजादी के 78 साल बाद कम से कम भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है कि तमाम आधुनिक उपकरणों ने लोकतंत्र और आजादी को सीमित किया है या सीमित करने का प्रयास किया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के नागरिक भी किसी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक दबाव में आजादी को सीमित करने के प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं या उसमें सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। एक तरफ सरकारें वाक व अभिव्यक्ति की आजादी को नियंत्रित करने के नए कानून ला रही हैं और संप्रेषण के नए माध्यमों को भी सज़ा तंत्र की मदद से नियंत्रित किया जा रहा है तो दूसरी ओर नागरिक समाज स्वेच्छा से अपनी आजादी गंवाने की प्रक्रिया में शामिल हो रहा है। अगर नागरिक समाज अपने अधिकारों और अपनी आजादी के प्रति सजग रहे तो वह सरकारी दमन का सफल प्रतिरोध कर सकता है। लेकिन मुश्किल यह है कि नागरिक समाज ही अपनी आजादी गंवाने में प्रत्यक्ष या परोक्ष योगदान कर रहा है। असल में भारत में आजादी को सिर्फ एक राजनीतिक अवधारणा बना दिया गया है। जब आजादी की बात होती है तो घूम फिर कर बात इस पर आ जाती है कि आपको सज़ा प्रतिष्ठान या शीर्ष पर बैठे राजनेता की आलोचना का अधिकार है या नहीं? यानी राजनीतिक बयान देने का अधिकार है या नहीं? माना जाता है कि अगर आपको राजनीतिक बयान देने का अधिकार है तो इसका मतलब है कि आप आजाद हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आजादी किसी राजनीतिक प्रतिष्ठान या किसी संविधान ने नहीं दी है या वह राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं है। मनुष्य आजाद पैदा होता है और उसके मौलिक अधिकार, जिसमें खाने पीने की आजादी, पहनावे की आजादी, अपने मूल्यों के साथ जीवन जीने की आजादी आदि शामिल हैं, उसको स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। लेकिन आजादी के 78 साल बाद यह स्थिति है कि कहीं खान पान की आजादी को नियंत्रित किया जा रहा है, कहीं पहनावे पर पाबंदी लगाई जा रही है, कहीं भाषा बोली को नियंत्रित किया जा रहा तो कहीं शादी की उम्र और पसंद को लेकर लोगों को कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। इस बुनियादी बात को ही भुला दिया गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सिर्फ बोलने की आजादी नहीं है, बल्कि अपनी पसंद का जीवन जीने की आजादी है। यह ध्यान रखने की जरुरत है कि नागरिकों की मौन या मुखर सहमति और नागरिक समाज की भागीदारी के बगैर लोकतंत्र और आजादी पर पहरा नहीं बैठाया जा सकता है और न उसे सीमित किया जा सकता है। इंदिरा गांधी के प्रयास को इस देश के नागरिकों ने असफल बनाया था। मगर आज स्थितियां बदल गई हैं। अगर आज महाराष्ट्र में वहां की सरकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मांस की बिक्री पर पाबंदी लगा रही है तो यह एक बड़े नागरिक समूह की सहमति के बगैर संभव नहीं है। पहली नजर में ऐसा लगेगा कि यह कितनी छोटी बात है! यह तर्क भी दिया जा रहा है कि अगर एक दिन मांसाहार नहीं करेंगे तो ज़्या आफत आ जाएगी! लेकिन यह छोटी बात नहीं है और न एक दिन की बात है। धार्मिक त्योहारों के सज़्मान में नागरिक समाज की ओर से इसकी शुरुआत हुई थी। कहा गया कि जैन समुदाय के पर्यूषण पर्व के मौके पर महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में मांस, मछली की दुकानें बंद रहेंगी। फिर कहा गया कि नवरात्रों में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में मांस, मछली की दुकानें बंद रहेंगी। इसके बाद कहा गया कि कांवड़ यात्रा के समय कांवड़ के पूरे रास्ते में मांसाहार की दुकानें बंद रहेंगी। और अब कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भी लोगों को मांसाहार की आजादी नहीं होगी। नागरिक समाज या एक धार्मिक समूह की ओर से किसी खास त्योहार के मौके पर पाबंदी लगाने की जो शुरुआत हुई थी वह सांस्थायिक होती जा रही है। सरकार अब कानून बना कर या आदेश पारित करके लोगों की फूड च्वाइस को नियंत्रित करना चाहती है। इसको छोटी बात नहीं माना जा सकता है। ज़्योंकि यह संयोग नहीं, बल्कि प्रयोग का हिस्सा है। एक बड़ा समूह इस पर चुप है, लेकिन इस चुप्पी में उसकी रक्षा नहीं है। आगे उसकी भी बारी आएगी। इसी तरह एक कथित संत अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों को लेकर एक बेहद आपज़िजनक बयान दिया। उन्होंने 25 साल की उम्र से पहले शादी की सलाह देते हुए कहा कि '25 साल की लड़की चार जगह मुंह मार चुकी होगी तो वह किसी रिश्ते को कैसे निभाएगी'। इस पर विवाद हुआ तो एक स्टैंडर्ड सफाई आई कि उनकी बातों को काट छांट कर प्रस्तुत किया गया। इसके बाद आए एक दूसरे कथित सज़्मानित संत प्रेमानंद जी महाराज आए तो उन्होंने अपना निष्कर्ष सुनाया कि, 'आजकल सौ में मुश्किल से चार पांच लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी सब ज़्वॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लगे रहते हैं'। इनके समर्थन में उतरे महंत राजू दास ने महिलाओं को लेकर कहा, 'समाज में अर्धनग्न घूम रहे हैं यह उचित नहीं है। मातृशक्ति पूजा के योग्य है लेकिन अर्धनग्नता नहीं, यह समाज में स्वीकार के योग्य नहीं है'। ये तीन बयान सिर्फ विवादित बयान नहीं हैं। इनकी भाषा तो बेहद भद्दी, अश्लील और आलोचना के योग्य है ही लेकिन इसके पीछे का पूरा विचार आजादी को प्रतिबंधित करने वाला है। दुर्भाग्य से यह काम कोई सरकार नहीं कर रही है, बल्कि सज़ा संरक्षित कथित संत इस तरह की बातें कर रहे हैं और नागरिक समाज उसका समर्थन और बचाव कर रहा है। अब सवाल है कि अगर 78 साल में हमारी आजादी मजबूत हुई है, हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है, तकनीक ने हमें अपने को अभिव्यक्त करने की बेहतर सुविधा दी है तो हम उसका ज़्या कर रहे हैं? हम इस प्रचार का हिस्सा बन रहे हैं कि लड़कियों को 25 साल की उम्र तक माता पिता की पसंद से शादी कर लेनी चाहिए नहीं तो उसको 'चार जगह मुंह मारने वाला' कहा जाएगा, उसको चरित्रहीन ठहराय जाएगा और रिश्ते निभाने की उसकी क्षमता पर सवाल उठाया जाएगा! यह एक बहुत बड़ा विषय है, जिसकी गहराई में जाएं तो बहुत पन्ने काले करने होंगे लेकिन मुज़्य रूप से यह स्त्रियों की पढ़ने लिखने, नौकरी करने, अपनी योग्यता साबित करने और उम्र के किसी भी पड़ाव पर अपनी पसंद से शादी करने या अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने की आजादी को सीमित करने का प्रयास है।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, रविवार 18 जनवरी 2026 | पृष्ठ-6

चीफ सेक्रेटरी ने ग्रामीण जल परियोजनाओं की समीक्षा की, तेजी से पूरा करने पर जोर दिया

भुवनेश्वर: चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग ने राज्य में चल रहे और बन रहे ग्रामीण पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स के स्टेटस का रिव्यू किया। मंगलवार को लोक सेवा भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई इस मीटिंग में पंचायती राज और पीने के पानी डिपार्टमेंट ने राज्य में पीने के पानी के सप्लाई प्रोजेक्ट्स का स्टेटस बताया। मीटिंग में पंचायती राज और पीने के पानी के कमिश्नर-कम-सेक्रेटरी, एस.एन. गिरीश के साथ-साथ अलग-अलग जिलों से डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर, असिस्टेंट चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल हुए, जिन्होंने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लागू होने और स्टेटस के बारे में जानकारी दी। चीफ सेक्रेटरी गर्ग ने चल रहे प्रोजेक्ट्स में कुछ इलाकों में पानी सप्लाई की दिक्कतों को हल करने, लोगों को पीने के पानी की सप्लाई पक्का करने और बन रहे प्रोजेक्ट्स को जल्दी पूरा करने पर जोर दिया है। मीटिंग में बताया गया कि राज्य में पीने के पानी की सप्लाई पक्का करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं।

सिंगल विलेज पाइप्ड वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट सिस्टम के तहत 18,233 प्रोजेक्ट्स लागू किए जा चुके हैं और 872 लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सोलर प्रोजेक्ट के तहत 6,435 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 2,189 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। राज्य में जल जीवन मिशन, वसुधा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ओडिशा मिनरल बेयरिंग एरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हस्त्र्रष्ट) के तहत स्त्रष्ट में मंजूर कुल 207 मेगा प्रोजेक्ट में से 26 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 181 पर काम चल रहा है।

मीटिंग में 50 परसेंट से ज़्यादा पूरे हो चुके 134 प्रोजेक्ट के स्टेटस का रिव्यू किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने अलग-अलग प्रोजेक्ट को पूरा करने में हो रही देरी के कारणों का पता लगाने के लिए डिविजनल सेक्रेटरी और इंजीनियर की मौजूदगी में डिटेल में रिव्यू किया। इनमें रायगढ़ ज़िले में 15, मयूरभंज ज़िले में 11 और सुंदरगढ़ ज़िले में 10 मेगा प्रोजेक्ट, जो लागू होने की प्रोसेस में हैं, के स्टेटस का रिव्यू किया गया। इसी तरह, बाकी सभी ज़िलों में मेगा पाइप्ड वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट के स्टेटस का रिव्यू किया गया और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरी निर्देश और सुझाव दिए गए। तय टारगेट के हिसाब से अलग-अलग प्रोजेक्ट को पूरा करने का सुझाव दिया गया है। पंचायती राज और पीने के पानी डिपार्टमेंट के कमिश्नर और सेक्रेटरी ने कहा कि प्रोजेक्ट्स को जल्दी पूरा करने के लिए रेगुलर इंटर-डिपार्टमेंटल रिव्यू और एक्शन लिए जा रहे हैं।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के एमआरडी विभाग द्वारा एक सप्ताह में दो रिकॉर्ड दर्ज

राउरकेला १७/०१ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के मैटेरियल्स रिकवरी विभाग (एमआरडी) ने एक सप्ताह के भीतर स्लैग प्रेषण में दो ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करके परिचालन उत्कृष्टता के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता को एक बार फिर प्रदर्शित किया है, जिससे दक्षता, समन्वय और टीम भावना के नए मानदंड स्थापित हुए हैं। 3 जनवरी, 2026 को विभाग ने एक ही दिन में 7,518.12 टन स्लैग की रिकॉर्ड तोड़ डिलीवरी की। इसी गति को बरकरार रखते हुए, एमआरडी टीम ने 7 जनवरी, 2026 को एक और उपलब्धि हासिल की और एक ही दिन में अब तक की सबसे अधिक 277 ट्रिप और 7981.58 टन स्लैग की डिलीवरी की। ये उपलब्धियां चुनौतीपूर्ण परिचालन परिस्थितियों में भी एमआरडी टीम के तन्यकता, अनुकूलन क्षमता और मजबूत निष्पादन को दर्शाती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों और विभाग के नेतृत्व से मिले निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन ने टीम को हर दिन अपनी सीमाओं को पार करने और उच्च लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एमआरडी टीम इस प्रदर्शन को बनाए रखने और राउरकेला इस्पात संयंत्र की समग्र सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के लिए 'सहया गृह' शेल्टर बनाएगा

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने मौजूदा सहया स्कीम के तहत दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के लिए खास शेल्टर होम बनाने के प्लान की घोषणा की है। प्रस्तावित सुविधाओं का नाम 'सहया गृह' होगा, जिसका मकसद कमज़ोर ग्रुप्स को सुरक्षित रहने की जगह, देखभाल और रिहैबिलिटेशन में मदद देना है। डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन इलाकों में ये घर बनाने के लिए फ़ीज़िबिलिटी रिपोर्ट मांगी गई है जहाँ इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बेनिफिशियरीज़ की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है।कलेक्टर्स से कहा गया है कि वे मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करें, संभावित बेनिफिशियरीज़ का असेसमेंट करें और सुविधाओं को बनाने के लिए एक्स्ट्रा ज़रूरतों की पहचान करें। स्पेशल सेक्रेटरी रजनी जानी ने एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन में मामले की अर्जेंटनेस पर ज़ोर दिया, और ज़िलों से जल्द से जल्द डिटेल्ड रिपोर्ट देने को कहा। जिन ज़िलों में ऐसी सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है, उन्हें डिपार्टमेंट को फॉर्मली यह बताने का निर्देश दिया गया है। आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि अगर लागू हो, तो अपने ज़िले में ऐसी सुविधा की ज़रूरत न होने की जानकारी इस डिपार्टमेंट को दें। इसे स्लस्ज्ञ त्रन्नश्वहज्ञ माना जा सकता है। सर्कुलर में कहा गया है। इस निर्देश में बालासोर, गंजम, जगतसिंहपुर, कंधमाल, नबरंगपुर, सुंदरगढ़ और सुबरनपुर जिले शामिल नहीं हैं, जिन्हें मौजूदा प्रक्रिया के दायरे से बाहर माना गया है।

जबरन शादियां स्वस्थ समाज को कमजोर करती हैं-हाई कोर्ट

कटक १७/०१ (संवाददाता): उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि किसी लड़की को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर करना एक अच्छे समाज के लिए सही नहीं है, जबकि अगर किसी लड़की को उसके माता-पिता ने ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया है, तो उसे अपने पति और माता-पिता दोनों से अलग, अकेले रहने की इजाज़त देना सही नहीं है। कोर्ट ने पुलिस को उसकी सुरक्षा पक्का करने का भी निर्देश दिया।

चीफ़ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मुरारी श्री रमन की डिवीज़न बेंच ने राज्य को माता-पिता को अपने फ़ैसले बड़े बच्चों पर थोपने के खिलाफ़ जागरूक करने के लिए सेंसिटाइज़ेशन प्रोग्राम चलाने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा, अब समय आ गया है जब समाज को इस बारे में सोचना चाहिए कि जब माता-पिता लड़कियों को ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर करते हैं। लड़की का फ़ैसला सबसे ज़रूरी है और माता-पिता को ऐसा कोई भी फ़ैसला लेने से पहले उसकी मंज़ूरी लेनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान काकटपुर पुलिस शादीशुदा महिला को कोर्ट लेकर आई थी। जजों ने उस महिला से बात की जिसने अपनी ज़बरदस्ती शादी और शादीशुदा ज़िंदगी में रहने में दिक्कत के बारे में बताया। उसने माता-पिता और ससुराल दोनों से दूर अकेले रहने की अपनी इच्छा भी बताई।

उसने साफ़-साफ़ कहा कि वह अपने पति या अपने माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वह अच्छी नौकरी करती है और आत्मनिर्भर है। उसने ज़ोर दिया कि बालिग होने के नाते, वह अपने फ़ैसले खुद लेने में पूरी तरह सक्षम है।

लड़की की बात सुनकर, कोर्ट ने मौजूदा हालात पर निराशा जताई, जहाँ माता-पिता अक्सर बच्चों, खासकर बेटियों पर अपनी मर्ज़ी थोपते हैं और बिना मर्ज़ी के उन्हें शादी के लिए मजबूर करते हैं। कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा कि बालिग लड़की का फ़ैसला सबसे ज़रूरी है और माता-पिता उसकी मर्ज़ी के बिना उसकी शादी नहीं कर सकते। बेंच ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह लड़की की सुरक्षित वापसी उसके घर पर सुनिश्चित करे और उसके माता-पिता या तथाकथित पति सहित किसी भी पार्टी से किसी भी तरह की दखलअंदाज़ी या रुकावट को रोके। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हम एक बालिग लड़की के फ़ैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि पुलिस उस लड़की की उसके घर पर सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और अगर उन्हें कोई घटना की सूचना मिलती है तो तुरंत कदम उठाएगी।

सिमिलिपाल नेशनल पार्क में मगरमच्छों की आबादी बढ़ी, दो साल से जारी गिरावट पलटी

बारीपदा १७/०१ (संवाददाता): सिमिलिपाल नेशनल पार्क में हाल ही में हुई मगरमच्छों की गिनती में रेप्टाइल की आबादी में मामूली लेकिन काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे रिज़र्व में चल रहे कंज़र्वेशन की कोशिशों को बढ़ावा मिला है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, मगरमच्छों की कुल संख्या पिछले साल के 81 से बढ़कर इस साल 84 हो गई है। यह गिनती 6 जनवरी से 8 जनवरी तक तीन दिनों में की गई, जिसमें पार्क के अंदर आठ बड़े पानी की जगहों पर 20 जगहों को कवर किया गया। इस दौरान नॉर्थ और साउथ सिमिलिपाल दोनों में फैले कुल 16 फ़ॉरेस्ट रेंज का सर्वे किया गया। जिन पानी की जगहों पर नज़र रखी गई, उनमें से वेस्ट देव नदी में मगरमच्छों की सबसे ज़्यादा गिनती दर्ज की गई, जहाँ अकेले 60 मगरमच्छ देखे गए। कुल गिनती में से, साउथ सिमिलिपाल फ़ॉरेस्ट डिवीज़न में 78, नॉर्थ सिमिलिपाल डिवीज़न में एक और रामतीर्थ क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर में पाँच मगरमच्छ पाए गए।जनगणना करने के लिए लगभग 30 टीमों में 100 से ज़्यादा वन कर्मियों को तैनात किया गया था, जिसमें रेंजर, फॉरेस्टर और फ्रंटलाइन स्टाफ शामिल थे, ताकि रिज़र्व की पूरी कवरेज हो सके। ऑफिशियल रिकॉर्ड बताते हैं कि हाल के सालों में सिमिलिपाल में मगरमच्छों की आबादी में उतार-चढ़ाव आया है। 2021 में पार्क में 81 मगरमच्छ थे, जो 2022 में बढ़कर 83 हो गए और 2023 में 86 के सबसे ज़्यादा लेवल पर पहुँच गए। हालाँकि, 2024 में यह संख्या घटकर 82 और 2025 में 81 हो गई। इस साल तीन मगरमच्छों की बढ़ोतरी से कुल गिनती 84 हो गई है, जो पिछले दो सालों में देखी गई गिरावट के ट्रेंड को असल में उलट देती है। वन अधिकारियों ने इस बढ़ोतरी का श्रेय लगातार संरक्षण की कोशिशों को दिया, खासकर रामतीर्थ मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर से सिमिलिपाल के अंदर अलग-अलग पानी की जगहों में हैचलिंग को रेगुलर छोड़ना। उन्होंने कहा कि लगातार मॉनिटरिंग और हैबिटैट प्रोटेक्शन के उपायों से आने वाले सालों में आबादी के और स्थिर और मज़बूत होने की उम्मीद है।

हॉट स्ट्रिप मिल-2 में इन-हाउस डिजिटल पहल एचएसएम-2 ईकनेक्ट ऐप किया गया लॉन्च

राउरकेला १७/०१ (संवाददाता): डिजिटल बदलाव और बेहतर परिचालन दक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, इन-हाउस विकसित डिजिटल पहल एचएसएम-2 ईकनेक्ट ऐप को हॉट स्ट्रिप मिल-2 (एचएसएम-2) में लॉन्च किया गया। इस डिजिटल एप्लिकेशन का उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक (एच.एस.एम एवं औक्सिलिअरी), श्री सुब्रत कुमार द्वारा महाप्रबंधक और अनुभाग प्रमुख (एचएसएम-2 विद्युत), श्री रंजीत कुजूर, महाप्रबंधक और अनुभाग प्रमुख (एचएसएम-2 संचालन), श्री दीपक कुमार यादव, और महाप्रबंधक और अनुभाग प्रमुख (एचएसएम-2 यांत्रिक),श्री सुब्रत कानूनगो के साथ-साथ एचएसएम-2 के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 3 जनवरी, 2026 को एचएसएम-2 सम्मेलन कक्ष में किया गया था। इस ऐप का लक्ष्य एचएसएम-2 में कम्युनिकेशन, रखरखाव समन्वय और जानकारी तक पहुंच को मजबूत करना है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस एप्लिकेशन की अवधारणा, डिजाइन और विकास पूरी तरह से इन-हाउस सहायक महाप्रबंधक एचएस एम-2 (विद्युत), श्री ज्योतिर्मय जेना द्वारा किया गया है, जो मिल के इनोवेशन, स्वामित्व और सिस्टम-संचालित कार्य संस्कृति पर मजबूत जोर को दर्शाता है। एक व्यापक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित, ॥स्न्2श्वष्टह्नह्नश्वष्टज्ञ ऐप एचएसएम-2 की दिन-प्रतिदिन की परिचालन और रखरखाव आवश्यकताओं के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यह एप्लिकेशन एक एकल इंटरफ़ेस पर महत्वपूर्ण जानकारी और वर्कफ़्लो को एक साथ लाता है, जिससे तेज़ी से निर्णय लेने, बेहतर समन्वय और संचालन में बढ़ी हुई पारदर्शिता को सक्षम किया जाता है। इस एप्लिकेशन में आधिकारिक उपयोग के लिए व्हाट्सएप जैसे इंटरफ़ेस के साथ एक सुरक्षित और संरचित आंतरिक संचार मॉड्यूल है, जो अनौपचारिक चैनलों पर निर्भरता को कम करता है। इसमें व्यवस्थित प्रवेश, ट्रैकिंग और रखरखाव गतिविधियों के भविष्य के संदर्भ के लिए एक क्षेत्रवार रखरखाव कार्य मॉड्यूल भी शामिल है। इसके अलावा, ऐप मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और मानक रखरखाव प्रथाओं (एसएमपी) तक आसान पहुंच प्रदान करता है, जो संचालन में एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करता है। तकनीकी दस्तावेज़ों तक त्वरित और विश्वसनीय पहुंच का समर्थन करने के लिए सहज ज्ञान युक्त नेविगेशन के साथ एचएसएम-2 चित्रों का एक केंद्रीकृत डिजिटल भंडार भी शामिल किया गया है। रखरखाव दक्षता को और मज़बूत करते हुए, एप्लिकेशन में एक व्यापक मोटर्स डेटाबेस है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत मोटर-वार तकनीकी जानकारी होती है, जो तेज़ी से समस्या निवारण और प्रभावी रखरखाव योजना में सहायता करती है। इसमें महत्वपूर्ण परिस्थितियों के दौरान त्वरित समन्वय के लिए आपातकालीन संपर्कों, संबंधित विभागों और प्रमुख अधिकारियों तक तैयार पहुंच के साथ एक महत्वपूर्ण संपर्क निर्देशिका भी शामिल है।

HSMwECONNECT का शुभारंभ बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और परिचालन उत्कृष्टता के लिए डिजिटल समाधानों का लाभ उठाने के लिए एचएसएम-2 की प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है। आवेदन के दैनिक संचालन और रखरखाव प्रबंधन के लिए एक अभिन्न उपकरण बनने की उम्मीद है, जो एचएसएम-2 संचालन की उत्पादकता, सुरक्षा और विश्वसनीयता में काफ़ी मदद मिलेगी।